LKS
RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928
www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

दिल्ली से प्रकाशित शुक्रवार 6 फरवरी 2026 लोकतंत्र का स्तंभ

कांग्रेस सांसद पीएम मोदी पर कर सकते थे हमला इसलिए मैंने उन्हें लोकसभा आने से रोका : बिरला

लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित

एजेंसी। नई दिल्ली

लोकसभा में लगातार हो रहे हंगामे के बीच गुरुवार को एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया, जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दावा किया कि उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आने से रोका था। स्पीकर का कहना था, कि उन्हें आशंका थी कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री पर शारीरिक हमला कर सकते हैं, जिससे लोकतंत्र की मर्यादा को गंभीर ठेस पहुंचती। स्पीकर बिरला ने कहा कि बुधवार को लोकसभा में हालात बेहद अप्रत्याशित और चिंताजनक हो गए थे। उन्होंने बताया कि यदि प्रधानमंत्री उस दिन सदन में आते और कोई अप्रिय घटना हो जाती, तो यह संसद और लोकतंत्र दोनों के लिए शर्मनाक स्थिति होती। इसी कारण उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे सदन में न आएं। अंततः प्रधानमंत्री मोदी के जवाबी भाषण के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। स्पीकर बिरला ने यह भी कहा, कि विपक्ष के कुछ सांसदों का आचरण लोकसभा के इतिहास में काले धब्बे के रूप में दर्ज हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ सांसद किसी गलत हरकत की योजना बना रहे थे। इसी वजह से प्रधानमंत्री के भाषण को टालना पड़ा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004 के बाद यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे सके और बिना उनके भाषण के ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया।

अपराजिता ने किया समर्थन : भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने भी स्पीकर बिरला के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर वास्तविक खतरा था और लोकसभा स्पीकर ने समय रहते सही निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री और देश की जनता को स्पीकर का आभार व्यक्त करना चाहिए।

विपक्ष ने आरोपों को खारिज किया : हालांकि विपक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने स्पीकर के दावे को गलत बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह निराधार है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर तीन महिला सांसद प्रधानमंत्री के पास जाकर खड़ी हो गईं तो क्या इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो गया? प्रियंका गांधी ने मीडिया से सवाल किया कि वे सरकार से यह क्यों नहीं पूछते कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दिया गया और इसके पीछे क्या आधार था।

लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित : इस पूरे घटनाक्रम के बीच हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है, प्रधानमंत्री का रास्ता रोकना, उन्हें घेर लेना? उन्होंने कहा कि संसद को जिस स्तर तक गिराया जा रहा है, उससे हर लोकतांत्रिक सोच रखने वाला व्यक्ति दुखी है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव बिना जवाब के ही ध्वनिमत से पारित

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्षी दलों के आठ सदस्यों के निलंबन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की मांग पर हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर 02 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। इस दौरान हंगामे के बीच सदन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को बिना जवाब के ही ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्हें कई स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है, लेकिन किसी को अनुमति नहीं दी गई। इस दौरान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपद यशो नाईक, सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री सुरेश गोपी ने अपने-अपने मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर सदन के बीचोंबीच पहुंच गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों को चेतावनी दी कि हाथों में तख्तियां लेकर आने पर उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिन्हें मतदान के बाद अस्वीकृत कर दिया गया। इस दौरान हंगामे के बीच ही धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपील की कि वे सदन को चलने दें और सभी को बजट पर बोलने का अवसर दें। उन्होंने कहा कि लगातार हंगामा करना सदन का अपमान है लेकिन विपक्षी सदस्यों के विरोध के चलते कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। गौरतलब है कि बुधवार को विपक्ष की महिला सदस्य बैनर लेकर प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंच गई थीं, जिसके चलते कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

बैंकों में 3.4 लाख करोड़ का सोना गिरवी, बैंकों का जोखिम बढ़ा

सोने की कीमतों में गिरावट से बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की चिंता बढ़ गई है। देश में गोल्ड लोन का चलन बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सोना गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं। हाल ही में सोने की कीमतों में तेज वृद्धि और उसके बाद तेजी के साथ दामों में गिरावट ने बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की ऋण व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 9 करोड़ लोगों ने सोना गिरवी रख कर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कर्ज लिया है। जिसके चलते लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपये मूल्य का सोना बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के पास गिरवी रखा हुआ है। सोने के दाम में हालिया गिरावट ने इस पूरे तंत्र को हिला दिया है। बैंक और वित्तीय संस्थान सोने की कीमत का 75 फ़ीसदी से 90 फ़ीसदी तक फाइनेंस कर देते हैं।

ऋण देने के जो नियम बना रखे हैं उसके अनुसार यदि दाम घटते हैं तो ऐसी स्थिति में ऋणधारक को ब्याज की मार्जिन मनी चुकानी पड़ती है। यदि वह मार्जिन नहीं दे पता है तो ऐसी स्थिति में बैंक और वित्तीय संस्थानों को अधिकार है कि वह सोने की नीलामी करके अपना पैसा वसूल कर लें। बीते वर्षों में सोने की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण गोल्ड लोन को सुरक्षित कर्ज मानते हुए बैंकों ने बड़े पैमाने पर सोने पर कर्ज को बढ़ावा दिया है। लोगों ने भी बढ़ी हुई कीमतों का फायदा उठाकर ज्यादा कर्ज लिया। कई मामलों में टॉप-अप लोन भी प्राप्त किया है। अब सोने के दाम अप्रत्याशित रूप से घटने के कारण गिरवी रखे गए सोने का मूल्य कम हो गया है। कर्ज की राशि से सोने की कीमत कम हो गई है। ऐसी स्थिति में बैंकों द्वारा कर्जदारों से मार्जिन मनी जमा करने या अतिरिक्त सोना गिरवी रखने का दबाव बढ़ाया जा रहा है।

समस्या यह है, गोल्ड लोन लेने वाले अधिकतर लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनके पास ब्याज और मार्जिन मनी के रूप में जमा करने के लिए अतिरिक्त नकदी नहीं है। जिससे वह वित्तीय संस्थान द्वारा मांगी गई मार्जिन मनी को जमा कर सकें। अर्थ विशेषज्ञों का कहना है, अगर कर्ज न चुकाने की स्थिति में बड़े पैमाने पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा सोने की नीलामी की जाएगी। ऐसी स्थिति में तो बाजार में सोने की आपूर्ति बढ़ेगी। जिससे सोने की कीमतों में और भी बड़ी गिरावट आ सकती है। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का घाटा बढ़ सकता है। इसका असर बैलेंस शीट पर भी पड़ेगा। सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह की तेजी और मंदी देखने को मिल रही है, उसने वित्तीय संस्थानों की चिंता को बढ़ा दिया है। शेयर बाजार में भी लगातार गिरावट का दौर चला। जिसके कारण वित्तीय संस्थानों को शेयर बाजार में भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बाजार में उपभोक्ता के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

लोकसभा में हंगामें के बीच विपक्षी नेताओं की अहम बैठक, निलंबित सांसदों का धरना, शिवराज और चिराग ने की राहुल की आलोचना

नई दिल्ली। लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन और लगातार हंगामें के बीच गुरुवार को संसद भवन में विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं की अहम बैठक हुई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में आयोजित इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इसी दौरान निलंबित सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राहुल गांधी को सदन में बोलने का अवसर दिए जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। सांसदों ने कहा कि जब तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने केंद्रीय राज्य मंत्री रवीनीत सिंह बिट्टू को 'गद्दार दोस्त' कहा, जबकि बिट्टू का परिवार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबकुछ न्यौछावर कर चुका है। पार्टी का विरोध करते-करते राहुल गांधी अब देश का विरोध करने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कुछ नेता केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान देते हैं और विभाजनकारी राजनीति करते हैं।

ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता, वेनेजुएला समेत किसी भी नए विकल्पों के मूल्यांकन के लिए तैयारः भारत

नई दिल्ली। भारत ने कहा है कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है। वह वेनेजुएला समेत किसी भी नए आपूर्ति विकल्प के वाणिज्यिक लाभों का मूल्यांकन करने के लिए तैयार है। भारत ने दोहराया कि वह ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने का पक्षधर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को यहां साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में एक बार फिर ऊर्जा जरूरतों और लाभकारी मूल्यों को निर्णय का आधार बताया। उन्होंने दोहराया कि भारत आपूर्ति में विविधता लाने का पक्षधर है। भारत की इस टिप्पणी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत रूसी तेल खरीदी बंद करने पर सहमत हो गया है। उल्लेखनीय है कि भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में व्यापार समझौता सम्पन्न हुआ है। समझौते के बाद अमेरिका ने भारतीय समानों पर लग रहा अतिरिक्त टैरिफ हटा लिया है। वहीं ट्रम्प ने दावा किया है कि भारत रूस से तेल खरीदी नहीं करेगा और वेनेजुएला को प्राथमिकता देगा। जायसवाल ने भारत अमेरिकी समझौते से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रवक्ता ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर कहा, "ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में सरकार ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से बयान दिया है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत की रणनीति रही है कि अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाजार स्थितियों और बदलते वैश्विक घटनाक्रम के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाए।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बोले शिवराज किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भारत–अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर विपक्ष के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह समझौता कूटनीति, विकास और राष्ट्रीय गरिमा का नया उदाहरण है और इसमें भारतीय किसानों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया गया है। चौहान ने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है और "झूठ की मशीन" बन चुका है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत रह गया है, जिससे भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भले ही अमेरिका की ओर से अधिक कृषि उत्पाद निर्यात की बात कही जा रही हो, लेकिन भारत ने अपने किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा की है। प्रमुख अनाज, फल, मोटे अनाज (बाजरा) और डेयरी क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं। एक बातचीत के दौरान कृषि मंत्री शिवराज ने कहा कि यह समझौता संघर्ष नहीं, बल्कि संतुलित और सशक्त संवाद का परिणाम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसान हमारे लिए केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि जीवनदाता हैं। किसानों के हित राष्ट्रहित हैं और उनकी रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की सेवा करना हमारे लिए ईश्वर की सेवा के समान है।

एचएएल ने वायु सेना को समय पर एलसीए मार्क-1ए की आपूर्ति करने का भरोसा दिया

एजेंसी। नई दिल्ली

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने वायु सेना को समय पर एलसीए मार्क-1ए की आपूर्ति करने का गुरुवार को भरोसा दिया है। आपूर्ति के लिए पांच तेजस मार्क-1 ए लड़ाकू विमान तैयार कर हैं, जिनके फायरिंग और मिसाइल ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं। वायु सेना इन फाइटर जेट की आपूर्ति स्वीकार करने से पहले इस साल मई में 'कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट' की समीक्षा करेगी। भारतीय वायु सेना ने एचएएल को दो किश्तों में 180 तेजस मार्क-1 ए लड़ाकू विमान के ऑर्डर दिए हैं। पहला ऑर्डर फरवरी 2021 में 83 लड़ाकू

फायरिंग और मिसाइल ट्रायल्स के बाद आपूर्ति के लिए पांच तेजस मार्क-1 ए लड़ाकू विमान तैयार

विमानों के लिए और दूसरा ऑर्डर पिछले साल सितंबर में 97 विमानों के लिए दिया गया था। एचएएल से दोनों सौदों के तहत वायु सेना को 141 लड़ाकू और 39 ट्रेनर विमान मिलने हैं। अभी तक एक भी विमान की आपूर्ति न होने पर वायु सेना प्रमुख कई मौकों पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इस बीच मई में पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन 'सिंदूर' के दौरान भी स्वदेशी लड़ाकू विमान की जरूरत महसूस की गई थी। दरअसल, एचएएल से वायु सेना को पहले बैच की आपूर्ति

मार्च 2025 तक होनी थी, लेकिन बाद में इस टाइमलाइन को बदलकर मार्च 2026 कर दिया गया। अब तक कोई अपडेट न मिलने से 31 मार्च की अंतिम समय सीमा तक आपूर्ति पर सवालिया निशान मंडरा रहा है, क्योंकि इसे अभी अपनी पहली उड़ान भरनी बाकी है। इस बीच एचएएल ने आज वायु सेना को भरोसा दिया है कि पांच एयरक्राफ्ट आपूर्ति के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसमें तय मानकों के अनुसार प्रमुख अनुबंधित क्षमताएं होंगी। एचएएल ने कहा कि नौ और एयरक्राफ्ट पहले ही बनाए और उड़ाए जा चुके हैं। अमेरिकी कंपनी जीई से इंजन मिलने पर इन एयरक्राफ्ट को भी आपूर्ति के लिए तैयार कर दिया जाएगा। एचएएल की ओर से बताया गया है कि विमानों की सभी डिजाइन और विकास के मुद्दे का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। जल्द से जल्द विमान आपूर्ति के लिए वायु सेना के साथ बातचीत किये जाने की तैयारी है। एचएएल को आज तक अमेरिकी कंपनी से पांच इंजन मिल चुके हैं और आगे भी इंजन की आपूर्ति जल्द से होने की उम्मीद है, इसलिए एचएएल ने भरोसा दिलाया है कि वह चालू वित्त वर्ष में विमानों की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।

अब तो वंदे भारत जैसी ट्रेनें फिर भी पंच्यूलिटी नहीं, रेलवे करे सुधारः पीएसी

नई दिल्ली। ट्रेनों के पंक्चुअलिटी में गिरावट देखने को मिल रही है। इस पर संसद की लोक लेखा समिति ने ट्रेनों की पंक्चुअलिटी को लेकर चिंता जताई है। लोकसभा में पेश रिपोर्ट 'ट्रेन ऑपरेशन में पंच्यूअलिटी और यात्रा समय' ने रेलवे की पोल खोल दी। 2021-22 में 90.48 प्रतिशत पंक्चुअलिटी 2023-24 में घटकर 73.62 फीसदी रह गई। 2024-25 (अगस्त तक) में मामूली सुधार हुआ है, औसत 78.67 फीसदी हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने लोकसभा में 10 साल के आंकड़े पेश किए। 2015-16 में 77.51 फीसदी से 2018-19 में 69.23 फीसदी तक कम हो गई। कोविड बाद 2021-22 में रिकवरी हुई, इसके बाद लगातार गिरावट आती गई है। इसमें श्रेणी ट्रेनें शामिल हैं, जिसमें मेल/एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, पैसेंजर, वंदे भारत भी शामिल हैं। समिति ने रेलवे बोर्ड को कड़े सुझाव दिए है। रिपोर्ट में आधुनिक कोचों की सराहना की गई, लेकिन 95 फीसदी यात्री नियमित ट्रेनों पर निर्भर है। पीएसी ने कहा कि समयबद्धता सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि रेलवे की विश्वसनीयता का भी प्रश्न है। रेलवे को पंच्यूलिटी में सुधार करे, यात्रियों को लेट ट्रेनों से छुटकारा मिलेगा।

श्रीलंका में पवित्र देवनीमोरी अवशेषों की प्रदर्शनी, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया आभार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके को कोलंबो स्थित पवित्र गंगारामय मंदिर में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अलग-अलग पोस्ट में कहा कि अप्रैल 2025 में अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि इन पूजनीय अवशेषों को श्रीलंका लाया जाएगा, ताकि वहां के लोग उन्हें नजदीक से देख सकें और श्रद्धा अर्पित कर सकें। यह कदम भारत और श्रीलंका के बीच गहरे सभ्यतागत और आध्यात्मिक

संबंधों का प्रतीक है, जो सदियों से साझा विरासत और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से पोषित होते आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पवित्र देवनीमोरी अवशेषों का श्रीलंका आगमन दोनों देशों के बीच स्थायी आध्यात्मिक बंधन का प्रमाण है। भगवान बुद्ध का शाश्वत संदेशकरुणा, शांति और सद्भाव मानवता को मार्गदर्शन देता रहेगा और सीमाओं से परे एकता और समझ को बढ़ावा देगा।

देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' का शुभारंभ

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को विज्ञान भवन से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी को आगामी तीन वर्षों के भीतर पूरे देश में शुरू किया जाएगा और यह टैक्सी चालकों के आर्थिक सशक्तीकरण का एक बड़ा माध्यम बनेगी। अमित शाह ने कहा कि फिलहाल भारत टैक्सी की शुरुआत गुजरात के कुछ शहरों के साथ दिल्ली और एनसीआर में की जा रही है लेकिन अगले तीन साल से भी कम समय में यह देश के हर

राज्य और प्रमुख शहरों में उपलब्ध होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक भारत टैक्सी टैक्सी चालकों के कल्याण का एक सशक्त मॉडल बनेगी। टैक्सी चालकों को 'सारथी' की संज्ञा देते हुए शाह ने कहा कि अभी तक उनकी टैक्सी का पहिया किसी और की कमाई करता था, लेकिन भारत टैक्सी के माध्यम से अब वही पहिया उनकी अपनी कमाई और समृद्धि के लिए घूमेगा। उन्होंने कहा कि सहकार टैक्सी जो भी मुनाफा कमाएगी, उसमें से तीन वर्ष बाद केवल 20 प्रतिशत राशि सहकार टैक्सी के पास रहेगी, जबकि शेष 80 प्रतिशत राशि प्रति किलोमीटर की औसत के आधार पर सीधे सारथियों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी। सहकार टैक्सी के मालिक भी स्वयं सारथी ही होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी देश की माताओं और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

अमेरिका खत्म करना चाहता है चीन का दबदबा भारत सहित 50 देशों को कर रहा एकजुट

एजेंसी। वाशिंगटन

अमेरिका के नेतृत्व में वैश्विक अर्थव्यवस्था और भविष्य की तकनीक को सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक रणनीतिक कदम उठाया गया है। चीन के वर्चस्व को चुनौती देते हुए अमेरिका ने करीब 50 देशों के एक शक्तिशाली ट्रेडिंग ब्लॉक का प्रस्ताव रखा है। इस वैश्विक गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिजों) के उत्पादन, प्रोसेसिंग और कीमतों को स्थिर रखना है ताकि अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला किसी एक देश के नियंत्रण में न रहे। 4 फरवरी, 2026 को वाशिंगटन में आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल के दौरान इस बड़े रोडमैप की घोषणा की गई, जिसे भविष्य की तकनीक पर नियंत्रण सुरक्षित करने की एक निर्णायक

वैश्विक रणनीति माना जा रहा है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्पष्ट किया कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार करना होगा, जिसमें टैरिफ और न्यूनतम कीमतों (फ्लोर प्राइस) के माध्यम से घरेलू और मित्र देशों के उत्पादकों की रक्षा की जा सके। वेंस ने कहा कि अमेरिका रेयर अर्थ और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बेसलाइन कीमतें तय करने पर विचार कर रहा है ताकि चीन जैसे देश कीमतों को कृत्रिम रूप से गिराकर प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर न कर सकें। उन्होंने इस ब्लॉक को साथी और सहयोगियों के बीच एक सुरक्षित जोन करार दिया, जिसका लक्ष्य किसी तीसरे पक्ष पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म करना और मित्र देशों के बीच संयुक्त उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस पहल का मुख्य केंद्र लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसी उन धातुओं को चीन के प्रभाव से मुक्त करना है, जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), सेमीकंडक्टर और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम के लिए अनिवार्य हैं। वर्तमान में चीन दुनिया के लगभग 70 प्रतिशत रेयर अर्थ खनन और 90% प्रोसेसिंग पर नियंत्रण रखता है और अक्सर कूटनीतिक विवादों के दौरान इनके निर्यात को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है।

चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षकों से कहा- पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करें

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले सामान्य, पुलिस तथा व्यय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। यहां के भारतीय निर्वाचन प्रबंधन संस्थान में गुरुवार से शुरू यह दो दिवसीय बैठक तीन चरणों में होगी। आयोग के अनुसार कुल 1,444 अधिकारियों को ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया है, जिनमें 714 सामान्य पर्यवेक्षक, 233 पुलिस पर्यवेक्षक और 497 व्यय पर्यवेक्षक शामिल हैं। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को संबोधित किया। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पर्यवेक्षकों को आयोग के मार्गदर्शक दीप के रूप में चुना गया है। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी 824 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी मशीनरी को ऊर्जा प्रदान करेगी और वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करें। निर्वाचन आयुक्त डॉ. संधू ने कहा कि पर्यवेक्षक मैदान में तैनात चुनाव अधिकारियों के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। उनकी आमद का व्यापक प्रचार हो और वे मतदाताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए पूरी तरह सुलभ रहें, ताकि किसी प्रकार के पक्षपात की धारणा भी न बने।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEU-TICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

खास खबर

कांग्रेस ने की डीटीसी कर्मचारी कल्याण कोष में हुए गबन की जांच की मांग

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) कर्मचारी कल्याण कोष में 22 लाख से अधिक राशि का डीटीसी के सोशल वेलफेयर विभाग के कर्मचारियों द्वारा गबन करने की जांच करने की मांग की। उन्होंने गुरुवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कर्मचारियों के कोष से जुड़े इस मुद्दे पर दिल्ली के उप-राज्यपाल और मुख्यमंत्री स्वयं हस्तक्षेप करके दोषी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करके अपराधिक और विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो उप-राज्यपाल अथवा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी सरकार के तहत डीटीसी विभाग में गड़बड़ी के इस मामले की जांच सीबीआई से भी करा सकते हैं। देवेंद्र यादव ने कहा कि लगभग 97 हजार करोड़ रुपये का घाटा झेल रही डीटीसी में कार्यरत कर्मचारियों के कल्याण कोष में 22 लाख की धोखाधड़ी होगी तो पब्लिक के लिए कर्तव्य निभाने में कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ्य होकर अपनी ड्यूटी कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच कराई गई तो डीटीसी में फैले संगठित भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा। देवेंद्र यादव ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से भी अधिक समय से डीटीसी में मुख्य सर्तकता अधिकारी (सीवीओ) का पद खाली है। डीटीसी में सीवीओ के पद को अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था के तहत विभागीय अधिकारी को नाममात्र रखा गया है, जबकि इस पर आईपीएस अधिकारी की पूर्णकालिक नियुक्ति होनी चाहिए ताकि विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों पर रोक लगाई जा सके। देवेंद्र यादव ने कहा कि डीटीसी कर्मचारी कल्याण कोष के फंड में धोखाधड़ी करने वाले उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने दस्तावेजों को अपनी स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि डीटीसी जैसे सार्वजनिक संस्थान में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए पारदर्शिता के साथ अधिकारियों की जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है।

रेलवे बोर्ड के सदस्य हरि शंकर वर्मा ने उत्तर रेलवे के प्रदर्शन की समीक्षा की

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड के सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास) हरि शंकर वर्मा ने गुरुवार को बड़ौदा हाउस स्थित उत्तर रेलवे मुख्यालय का दौरा किया और जोन के परिचालन प्रदर्शन और रणनीतिक दिशा की समीक्षा की। विभागाध्यक्षों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान हरि शंकर वर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि रेल संचालन के दौरान संरक्षा और सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। कार्य संस्कृति के संबंध में कड़े निर्देश देते हुए उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को औपनिवेशिक मानसिकता त्यागने और सेवा वितरण में पूर्णतः ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और कार्यशैली में नवीन एवं अभिनव दृष्टिकोण अपनाने पर भी जोर दिया। वर्मा ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "भारतीय रेलवे 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प के लिए विकास का इंजन बनेगी।" उन्होंने कहा कि प्रत्येक रेलवे अधिकारी का प्रदर्शन इसी व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य से प्रेरित होना चाहिए। वर्मा ने परिचालन और वाणिज्यिक विभाग के अधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की, जिसमें मंडल स्तर के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। सत्र के दौरान उन्होंने युवा अधिकारियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने फील्ड में अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों को सुना और परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इससे पहले उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक (पीसीओएम) डॉ. मोनिका अग्निहोत्री और प्रमुख मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (पीसीसीएम) प्रवीण पांडे ने उनका औपचारिक स्वागत किया।

कई राज्यों में कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने की प्रवृति पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कई राज्यों में कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त करने की प्रवृति पर असंतोष जताते हुए यूपीएससी को अधिकार दिया कि वो राज्यों को समय पर प्रस्ताव भेजने के लिए कहे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कई राज्य सरकारें प्रकाश सिंह मामले में तय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए समय पर यूपीएससी को नाम नहीं भेजतीं और उसकी जगह कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त कर देती हैं। दरअसल, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था जिसमें यूपीएससी को राज्य सरकार की ओर से भेजे गए नामों पर कार्रवाई करने को कहा गया था। यूपीएससी ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने डीजीपी चयन में काफी देरी की। यूपीएससी ने कहा कि तेलंगाना के अंतिम नियमित डीजीपी अनुराग शर्मा 2017 में सेवानिवृत हुए थे और उसके बाद राज्य ने लंबे समय तक कोई सिफारिश नहीं भेजी। राज्य सरकार ने अप्रैल, 2025 में सिफारिश भेजी। इस पर यूपीएससी ने 2017 से चली आ रही देरी का हवाला देते हुए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और पहले उच्चतम न्यायालय से स्पष्टीकरण लेने की बात कही। यूपीएससी का कहना है कि तेलंगाना के अलावा दूसरे कई राज्य हैं जो ऐसी देरी की रणनीति अपना रहे हैं।

शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ ने शाहपुर जट गांव में मनाई 649वीं जयंती

» खलीफा सोहन वीर कैन ने बनाया जन्मदिन

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ की ओर से संत श्री गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती समारोह का आयोजन अम्बेडकर चौपाल शाहपुर जट गांव नई दिल्ली में किया गया।इस भव्य-विराट और ज्ञानवर्धक आयोजन के मुख्य अतिथि पीठ के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री आत्माराम परमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष धर्मवीर,राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत कुमार,असम प्रांताध्यक्ष भावेन्द्र, दिल्ली प्रांताध्यक्ष मनोज कुमार आजाद,प्रो हंसराज सुमन,राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दक्षिण विभाग कार्यवाह संजीव त्यागी और क्षेत्रीय विधायिका शिखा राय रहे ।जयंती के उपरांत पीठ के दिल्ली प्रांत के उपाध्यक्ष खलीफा सोहन वीर कैन का जन्मदिन भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम का आरंभ गुरु जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके पश्चात सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया।अपना संबोधन प्रस्तुत करते हुए आत्माराम परमार ने पीठ की संकल्पना, निर्माण और उसके उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला।उन्होंने जालंधर पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर "श्री गुरु रविदास जी महाराज हवाई अड्डा"करने और डेरा सचखंड बल्लां,जालंधर के संत श्री निरंजन दास जी महाराज को पद्मश्री देने के लिए प्रधानमंत्री जी का पीठ और समस्त रविदासिया समाज की ओर से आभार व्यक्त किया।राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत जी ने पीठ के अभी तक किए गए कार्यों और आगामी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। प्रो हंसराज सुमन जी ने अपने वक्तव्य में एक महत्वपूर्ण बात रखते हुए कहा कि भारत के किसी एक विश्वविद्यालय का नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर होना चाहिए। दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष मनोज आजाद ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा की यह गुरु जी की जन्म जयंती का 650 वां वर्ष चल रहा है।इस वर्ष में हम दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर गुरु जी से संबंधित इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।संजीव ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को रविदास जयंती की बहुत-बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रो मनोज कुमार के ने कहा कि गुरु रविदास जी के साहित्य को सभी शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। सभी अतिथियों ने खलीफा सोहन वीर कैन को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई और उपहार भी दिए। विभिन्न संगठनों में दक्षिण विभाग मंत्री विश्व हिन्दू परिषद- राधाकृष्णन;जिला धर्मप्रसार कालका जी-अनिल;कालका जी जिला सद्भाव राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ-सतीश;कालका जी जिला मंत्री सेवा भारती -सुनीता बॉस;पीठ के पदाधिकारियों में:- महामंत्री - सुनीता पॉल,उपाध्यक्ष- निर्मल कुमार कैम,अनिल कुमार,मेहर सिंह, बालकृष्ण ,मंत्री -डॉ घनश्याम,डॉ संदीप रंजन,सुरेश तंवर, जिलाध्यक्ष- प्रीति विद्यार्थी- करोल बाग, ज्योति- नई दिल्ली, किशन कुमार- शाहदरा। अन्य गणमान्य व्यक्तियों में अशोक कुमार,सौरभ कुमार ।शाहपुर जट गांव के ज्ञानचंद ,रमेश तंवर,मेहर चंद तंवर, रत्नलाल, धनपत राय, नंदकिशोर, सुरेश, जयकिशन,लक्ष्मण नारायण,महेश, मोहनसिंह कैन, मुकेश कैन,अमन चौधरी,अक्षय चौधरी आदि महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सभी अतिथियों और लोगों का धन्यवाद पीठ के मंत्री मास्टर योगेश जी ने किया। इस आयोजन में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की।

मोदी सरकार ने ठान लिया है कि विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाना है- खरगे

लोकतंत्र की शान

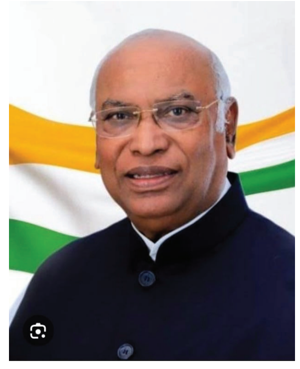

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर संसद में विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने और तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के लगातार कहने के बावजूद पिछले चार दिनों से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। मोदी सरकार ने ठान लिया है कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों के साथ वॉकआउट करने के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विपक्ष संसद में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, युवाओं के रोजगार और ट्रंप के बयान पर अपनी बात रखना चाहता था। सभी विपक्षी दलों ने ये तय किया था कि अगर लोकसभा में नेता विपक्ष को बोलने दिया गया, तो वह प्रधानमंत्री की बात जरूर सुनेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष ने जानबूझकर दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं को बोलने से रोका। सत्ता पक्ष ने ठान लिया है कि विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाना है। खरगे ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर देश के किसानों के हितों का बलिदान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप कहते हैं, मोदी वही करते हैं। मोदी ने ट्रंप के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। खरगे ने सदन में सत्ता पक्ष द्वारा पूर्व प्रधानमंत्रियों के प्रति इस्तेमाल की गई भाषा पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि देश के लिए कुर्बानियां देने वाले और देश को आजादी दिलाने वाले महान नेताओं के लिए संसद में एक व्यक्ति द्वारा अपशब्द कहे जाते हैं, उसे माइक दिया जाता है और पूरा सत्ता पक्ष चुपचाप सुनता है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत बनाया और इंदिरा गांधी जी ने देश में एक नई जागृति पैदा की। उन्होंने चेतावनी दी कि महापुरुषों के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

माउंट एकांकागुआ फतेह करने जाने वाले दल को रक्षा मंत्री ने किया रवाना

शारीरिक, मानसिक दृढ़ता देश के सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहियों की पहचान: राजनाथ सिंह

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से अर्जेंटीना में माउंट एकांकागुआ फतेह करने जाने वाले संयुक्त पर्वतारोही दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने पर्वतारोहण को टीम वर्क और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा बताया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनआईएम और जेआईएमएंडडब्ल्यूएस के अभियान की सराहना करते हुए कहा कि ये संस्थान अपने कर्मियों को साहस, दृढ़ता और संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है। टीम को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि इस दुर्गम शिखर पर चढ़ना न केवल शारीरिक सहनशक्ति की परीक्षा है, बल्कि नेतृत्व, टीम वर्क और मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहियों की पहचान है। माउंट एकांकागुआ फतेह के निकली छह सदस्यीय टीम में अत्यधिक प्रशिक्षित प्रशिक्षक भी शामिल हैं। इस दल में कर्नल हेम चंद्र सिंह, कैप्टन संथोष कुमार, दीप बहादुर सही, विनोद गुसाईं, नायब सुबेदार भूपिंदर सिंह और हवलदार रमेश कुमार शामिल हैं। यह यात्रा 6 फरवरी, 2026 से शुरू होगी और अभियान महीने के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

चीन में सबसे ज़्यादा मशहूर भारतीय, जो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले

लोकतंत्र की शान, सुनील नेगी

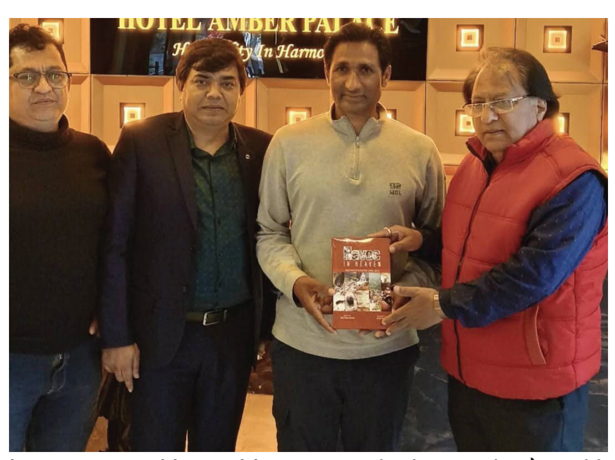

अपने दोस्त और मशहूर एंटरप्रेन्योर, श्री देव रतूड़ी के बुलावे पर गुड़गांव में उनके नए होटल जाने का मौका मिला, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। श्री रतूड़ी चीन में रेस्टोरेंट की एक सफल चेन चलाते हैं और उन्होंने वहां कई फिल्मों में काम किया है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल गांव में एक साधारण परिवार से लेकर एक सफल बिजनेसमैन बनने तक, जीवन में उनकी कड़ी मेहनत और लगन की कहानी अद्भुत है। उनका बचपन और जवानी चुनौतियों से भरी थी और सीमित शिक्षा के अवसरों के साथ, उन्होंने एक सच्चे बहादुर की तरह संघर्ष किया, पहले एक डेयरी में दूधवाले के रूप में काम किया, फिर ड्राइवर और वेटर के रूप में। मौका तब मिला जब वह एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए चीन गए। धीरे-धीरे उन्होंने नीचे से शुरुआत करके एक कंपनी में जीएम का पद हासिल किया। उन्होंने चीनी भाषा अच्छी तरह सीखी और मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग ली, और उनके दिल में अपनी मातृभूमि भारत और अपनी संस्कृति के लिए गर्व था। उन्होंने एक इनोवेटिव इंडियन थीम वाला फूड पवेलियन खोला, जिसमें भारतीय स्वाद और संस्कृति को खुलकर दिखाया गया। जल्द ही उनका आइडिया और बिजनेस रेस्टोरेंट की चेन के रूप में फला-फूला और उन्हें एक सफल एक्टर और प्रशिक्षित मार्शल आर्ट्स और योग विशेषज्ञ के रूप में पहचान मिलने लगी। उनके जीवन पर एक चैप्टर चीनी स्कूल की किताबों में शामिल किया गया। देव रतूड़ी कभी भी अपनी भारतीय और उत्तराखंड की जड़ों को नहीं भूले और उन्होंने चीन में कई साथी उत्तराखंडियों को नौकरी दिलाने में मदद की। आज वह उत्तराखंड और भारत में सामाजिक कामों में अपना कीमती समय बिताते हैं, इस तरह उस समाज को वापस देते हैं जहां उनकी कड़ी मेहनत और मजबूत इच्छाशक्ति आखिरकार भीड़ से अलग दिखी। उन्होंने गुड़गांव में एक खूबसूरत थीम - ह्यूमैनिटी इन हार्मनी के साथ अपना नया होटल "अंबर पैलेस" लॉन्च किया है, जिसे बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है और यहां का खाना ग्लोबल स्टैंडर्ड का है। मैं, मंजुल थपलियाल सीईओ- विजन अहेड फाउंडेशन और प्रेसिडेंट- ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क और श्री सुनील नेगी, डायरेक्टर- प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और सीनियर जर्नलिस्ट ने श्री देव रतूड़ी के साथ तीन घंटे बिताए और उत्तराखंड और भारत में अपनी जड़ों के लिए योगदान देने के लिए सार्थक सहयोग पर चर्चा की। श्री थपलियाल ने उन्हें AMON के बारे में जानकारी दी, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बिजनेस, सांस्कृतिक और नैतिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। श्री नेगी ने उन्हें अपनी किताब "हैवॉक इन हेवन" भेंट की, जो केदारनाथ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर आधारित है, जिन्होंने अतीत में उत्तराखंड को प्रभावित किया है। हमने मिलकर सामाजिक प्रभाव और तालमेल के लिए आपसी प्रयासों पर चर्चा की ताकि हमारी पहाड़ी संस्कृति को और भी बेहतर तरीके से बढ़ावा दिया जा सके। इस खूबसूरत होटल में ज़रूर जाएं जो श्री देव रतूड़ी के संघर्ष और सफलता की कहानी कहता है।

प. बंगाल सरकार कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते का 25 फीसदी 6 मार्च तक भुगतान करे : सुप्रीम कोर्ट

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वो अपने कर्मचारियों को 2008 से 2019 तक के महंगाई भत्ते का भुगतान करे। जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली बेंच ने महंगाई भत्ते को कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार करार देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वो महंगाई भत्ते के बकाया का 25 फीसदी 6 मार्च तक भुगतान करे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कल्याणकारी राज्य में महंगाई भत्ता कर्मचारियों की सुरक्षा का एक उपाय है। महंगाई भत्ता बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों को बचाता है। ये एक अतिरिक्त लाभ नहीं है, बल्कि न्यूनतम जीवनस्तर को बनाये रखने का उपाय मात्र है। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को बकाये महंगाई भत्ते का भुगतान किस तरह और किस समय सीमा में किया जाएगा, इसे तय करने के लिए जस्टिस इंदू मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। कमेटी में जस्टिस इंदू मल्होत्रा के अलावा झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी कमेटी के सदस्य होंगे। इस कमेटी में भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक (सीएजी) या उनकी ओर से मनोनीत एक वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। उच्चतम न्यायालय ने इस कमेटी को 16 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। 16 मई को ही मामले की अगली सुनवाई होगी।

कार्यालय: ग्राम पंचायत सदिकापुर सरैया, विकास खण्ड महोली, जनपद सीतापुर (उ.प्र.)

पत्रांक मेमो /पंचम वित्त /15 वाँ वित्त / मनरेगा / निविदा वर्ष 2026-27

निविदा आमंत्रण सूचना (अल्पकालीन)

समस्त पंजीकृत निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है के पंचम राज्य वित्त, 15 वां वित्त / मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत सदिकापुर सरैया आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुमोदित कार्य योजना वर्ष 2026-27 की निम्नलिखित परियोजनाओं में प्रयुक्त सामग्री हेतु टेण्डर फार्म पर मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं निविदाये टेण्डर दिनांक 06/02/2026 से दिनांक 13/02/2026 तक प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक ग्राम पंचायत मुख्यालय से प्राप्त कर व भरकर पेटिका में डाली जायेगी। प्राप्त निविदायें दिनांक 13/02/2026 अपरान्ह 4 बजे सक्षम अधिकारी के समक्ष खोली जायेगी।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	योजना	प्राक्कलन के अनुसार कुल लागत-	सामग्री	सामग्री लागत
2.	सदिकापुर सैरया में रेवाना विद्यालय में MDM रोड निर्माण	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	3,57,464.00	मौरंग, बालू, सीमेंट, ईंटा, लोहा आदि	2,77,405.00 लेवर- 20705

प्राप्त निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत / निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी निहित होगा। निविदा स्वीकृत होने पर आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र देना होंगा। भुगतान के पूर्व सामग्री के बिल से सभी देय करों की कटौती निम्नानुसार की जायेगी। सामग्री की पीडब्लूडी के अनुरुप ही प्राक्कलन में प्रविधानित है।

सचिव
जितेंद्र कुमार
ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी
विकास खण्ड महोली, सीतापुर, उ.प्र.

प्रधान
श्रीमती सरोज कुमारी
ग्रा.पं. सदिकापुर सरैया

कार्यालय: ग्राम पंचायत अमिलिया, विकास खण्ड महोली, जनपद सीतापुर (उ.प्र.)

पत्रांक मेमो /पंचम वित्त /15 वाँ वित्त / मनरेगा / निविदा वर्ष 2026-27

निविदा आमंत्रण सूचना (अल्पकालीन)

समस्त पंजीकृत निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है के पंचम राज्य वित्त, 15 वां वित्त / मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत अमिलिया आवंटित धनराशि के सापेक्ष अनुमोदित कार्य योजना वर्ष 2026-27 की निम्नलिखित परियोजनाओं में प्रयुक्त सामग्री हेतु टेण्डर फार्म पर मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं निविदाये टेण्डर दिनांक 06/02/2026 से दिनांक 13/02/2026 तक प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक ग्राम पंचायत मुख्यालय से प्राप्त कर व भरकर पेटिका में डाली जायेगी। प्राप्त निविदायें दिनांक 13/02/2026 अपरान्ह 4 बजे सक्षम अधिकारी के समक्ष खोली जायेगी।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	योजना	प्राक्कलन के अनुसार कुल लागत-	सामग्री	सामग्री लागत
1.	संविलियन विद्यालय में MPM रोड निर्माण	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	4,96,750.00	मौरंग, बालू, सीमेंट, ईंटा, लोहा आदि	3,88,326.25

प्राप्त निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत / निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी निहित होगा। निविदा स्वीकृत होने पर आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र देना होंगा। भुगतान के पूर्व सामग्री के बिल से सभी देय करों की कटौती निम्नानुसार की जायेगी। सामग्री की पीडब्लूडी के अनुरुप ही प्राक्कलन में प्रविधानित है।

सचिव
जितेंद्र कुमार
ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी
विकास खण्ड महोली, सीतापुर, उ.प्र.

प्रधान
श्रीमती रीना देवी
ग्रा.पं. अमिलिया

संक्षिप्त समाचार

जिला कोर्ट का तीव्र गति से निर्माण किया जाए : अरुण कुमार सिंह देशवाल प्रशासनिक न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट

लोकतंत्र की शान : सैय्यद कुमैल ज़ैदी : संभल। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने जनपद के जिला न्यायालय व उपभोक्ता फॉर्म की अधिकृत जमीन का निरीक्षण किया। अस्थाई जिला कोर्ट में कम्प्यूटरीकृत कॉपिंग सेंटर का उद्घाटन किया। गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने सर्वप्रथम प्रशासनिक

न्यायामूर्ति द्वारा कम्प्यूटरीकृत कॉपिंग सेन्टर का उत्तर प्रदेश में पहली बार उद्घाटन किया गया। उसके पश्चात् प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा सम्भल में प्री-फैवरिकेटिड बाह्य न्यायलय व ऑफिस का उद्घाटन किया गया।तत्पश्चात् प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा बहजोई में अधिगृहित नवीन भूमि जिसमें जनपद न्यायालय का नवीन मुख्यालय बनना प्रस्तावित है का निरीक्षण कर तीव्र गति से निर्माण करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये। उसके पश्चात् प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सम्भल का निरीक्षण किया गया व उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सम्भल के लिये नवीन भूमि का भी निरीक्षण किया गया व विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये। प्रशासनिक न्यायमूर्ति का यह निरीक्षण न्यायिक कार्य प्रणाली की नवीन अधोसंरचना में तीव्र गति व लम्बित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के लिये आवश्यक कदम साबित होगा। इस दौरान जनपद न्यायाधीश डा विदुषी सिंह, बार एसोसिएशन के अधिवक्ता आदि शामिल रहे।

अमरोहा पुलिस ने महिला की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहाः अमरोहाः अमरोहा देहाथ थाना क्षेत्र के पचोकरा गांव में एक महिला की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है यह घटना बुधवार दोपहर दिनदहाड़े हुई थी पुलिस के अनुसार आरोपी धीरज के मृतका रूबी से करीब

4 साल से प्रेम संबंध थे, पिछले 4 महीने से महिला ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी थी आरोपी धीरज महिला से बात करना चाहता था लेकिन बात न करने पर उसने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी, मृतका की पहचान गांव निवासी दलित नरेंद्र कुमार की 35 वर्षीय पत्नी रूबी के रूप में हुई है, आरोपी 22 वर्षीय धीरज पड़ोस में रहने वाले बृजपाल का बेटा है और बाल्मीकि समाज से है, उसने अपने घर के आगे ही रूबी पर ताबड़तोड़ चाकू से बार कर हत्या कर दी थी और बाद में पड़ोस के घर में छिप गया था, घटना के बाद मृतका के परिजनों ने आरोपियों के घरों में तोड़फोड़ की थी जिससे गांव में तनाव की स्थिति बन गई, स्थिति को देखते हुए एसपी सहित 5 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची करीब 6 घंटे की कोशिश के बाद गुस्साआए लोगों को शांत करा कर शव को कब्जे में लिया गया,वहीं गुरुवार को अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए बताया कि मामले में मुख्य आरोपी धीरज और उसके सगे भाई नीरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है 1

संभल की सेवा में समर्पित एक मजबूत नाम-चौधरी मुशीर अली खान

समाजसेवा और जनहित के कार्यों में निभा रहे अग्रणी भूमिका

लोकतंत्र की शान : संभल : नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पति चौधरी मुशीर अली खान आज क्षेत्र में एक ऐसे समर्पित समाजसेवी के रूप में पहचाने जा रहे हैं, जिनकी प्राथमिकता हमेशा जनता की सेवा और विकास रही है। नगर पालिका क्षेत्र के साथ-साथ वे संभल विधानसभा क्षेत्र से जुड़े जनहित के मुद्दों पर भी लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। चौधरी मुशीर अली खान नगर में सफाई व्यवस्था, नालियों की मरम्मत, सड़क सुधार, स्ट्रीट लाइट, पेयजल समस्या और जरूरतमंद परिवारों की मदद जैसे कार्यों में हमेशा

आगे नजर आते हैं। जनता के बीच रहकर समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से समन्वय करना उनकी कार्यशैली की पहचान बन चुकी है। इसके अलावा वे ऐसे कई कार्यों पर भी ध्यान दे रहे हैं, जो सामान्यतः विधायक स्तर के अंतर्गत आते हैं—जैसे प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण, शिक्षा संस्थानों की बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती, जल निकासी की स्थायी व्यवस्था और प्रशासनिक स्तर पर जनसमस्याओं का समाधान। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि चौधरी मुशीर अली खान विधायक बनते हैं, तो वे संभल विधानसभा क्षेत्र में अब तक के मुकाबले सबसे अधिक विकास कार्य कराएंगे। जनता का मानना है कि उनका अनुभव, जमीनी पकड़ और हर वर्ग से सीधा संवाद उन्हें एक प्रभावी जनप्रतिनिधि बना सकता है। लगातार बढ़ती जनस्वीकृति यह दर्शाती है कि चौधरी मुशीर अली खान सेवा, संवेदना और विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। संभल की जनता उन्हें एक ऐसे मजबूत नाम के रूप में देख रही है, जो पद से नहीं, बल्कि काम से पहचान बनाता है।

यूपी में एक लाख ग्रामीण महिलाओं के जीवन में मिठास घोलेगा शहद

लोकतंत्र की शान : लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और खेती-किसानी को नई ताकत देने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मधुमक्खी पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं शहद उत्पादन के साथ-साथ फसलों की उत्पादकता भी बढ़ाएंगी। योजना के अंतर्गत आगामी तीन वर्षों में एक लाख महिला मधुमक्खी

पालक तैयार की जाएंगी। इसके तहत प्रत्येक महिला उद्यमी की आय में प्रति वर्ष एक लाख रुपये तक की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। मधुमक्खियों द्वारा परागण से गेहूं, सरसों, दलहन-तिलहन और बागवानी फसलों की पैदावार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी, जिससे किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

यूपी का शहद वैश्विक पहचान बनाएगा-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन विलेज के तहत अब यूपी का शहद वैश्विक पहचान बनाएगा। महिलाएं शहद का अपना ब्रांड विकसित करेंगी और शहद व अन्य उत्पादों के विपणन से प्रदेश के आर्थिक विकास में साझीदार बनेंगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और महिलाओं का आत्मनिर्भरता का सपना साकार होगा। इस योजना के जरिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और उद्यमियों को बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि यूपी का शहद देश-दुनिया में गुणवत्ता और भरोसे की पहचान बने।

किसानों को अब 5 मिनट में ई-केसीसी से ऋणः सीएम योगी

लोकतंत्र की शान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस ने उत्तर प्रदेश में ऋण स्वीकृति की तस्वीर ही बदल दी है। अन्नदाता किसान जब पहले किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ऋण लेने जाता था, तो 25 दिन से लेकर एक महीने तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज वही किसान ई-केसीसी के माध्यम से मात्र पांच मिनट में ऋण सुविधा प्राप्त कर रहा है। वर्ष 2026-27 के लिए जो हमारा कृषि ऋण 3 लाख करोड़ है, यह पहले की तुलना में 13 फीसदी बढ़ा है। यही सुशासन है और इसी दिशा में हमें और मजबूती से आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को लोकभवन में आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 के विमोचन के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज सरकार और अन्नदाता किसान मिलकर सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग खेती में कैसे किया जाए। प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से केंद्रीय बजट में एआई एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है और उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन) को मंच पर सम्मानित भी किया।

दिव्यांग और महिला नेतृत्व वाले एफपीओ बने प्रदेश के लिए रोल मॉडल- मुख्यमंत्री ने कहा कि संगोष्ठी में जो मॉडल प्रस्तुत किए गए, वे पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा हैं। दिव्यांगजनों द्वारा संचालित कसया मिल्क प्रोड्यूसर एफपीओ, जिसमें 1,005 सदस्य हैं, इसका जीवंत उदाहरण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, जिन्हें पहले कमजोर माना जाता था, दिव्यांगजनों ने अपनी मेहनत और क्षमता से नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह आंखें खोलने वाला काम है और इसके लिए वे सभी अभिनंदन के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने मथुरा की 750 महिलाओं वाली सरसों उत्पादन कंपनी का उल्लेख करते हुए कहा कि मैंने स्वयं उनकी प्रदर्शनी देखी है। किस तरह मस्टर्ड ऑयल को प्रोसेसिंग से जोड़कर महिलाओं ने बेहतर मुनाफा कमाया, यह पूरे प्रदेश के लिए सीख है। सरकार इस तरह के प्रयासों को हर स्तर पर सहयोग देगी।

महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले 4 आरोपियों में से मुख्य आरोपीय गिरफ्तार

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः गुरुवार को हसनपुर कोतवाली पुलिस द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़ करने के आरोपियों से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, बता ते चले कि नगर की रहरा रोड स्थित गोकुलधाम कॉलोनी की मुख्य सड़क पर अवैध रूप से रखें खोका स्वामी सहित चार लोगों के खिलाफ मोहल्ले की महिलाओं से छेड़खानी व अभद्र टिप्पणी को लेकर देर रात पुलिस ने 4 लोगो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था जिसमें से गुरुवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी रिहान पुत्र जहीर को देर रात ही गिरफ्तार कर लिया तथा अन्य आरोपी हारून पुत्र जहूर तथा रिहान के दो भाइयों की तलाश जारी है, बताते चले कि मामले में 3 दिन से पुलिस टाल मटोल कर रही थी तथा बुधवार को मोहल्ले की महिलाओं ने पलायन तथा इच्छा मृत्यु के पोस्टर भी अपने घरों पर चश्पा किए थे, तथा बुधवार को पीड़ित के रिश्तेदार एवं लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने हसनपुर कोतवाली में पहुंचकर

जमकर हंगामा कांटा और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की थी इसके बाद पुलिस ने दो नाम जद व दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें से पुलिस ने मुख्य आरोपी रिहान पुत्र जहीर को गिरफ्तार कर लिया गुरुवार को यह जानकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज कुमार त्यागी ने दी 1

जिलाधिकारी ने तहसील महोली का किया निरीक्षण

परिसर मे बने उपनिबंध कार्यालय की देखी गुणवत्ता दिए निर्देश

लोकतंत्र की शान , देवेंद्र सिंह

सीतापुर । जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0 ने आज आदर्श तहसील महोली परिसर के अन्दर निर्माणाधीन उप निबंधक कार्यालय महोली के भवन के निर्माण कार्य को देखा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने भवन के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को देखते हुये निर्देश दिये कि भवन में बेहतर सामग्री का उपयोग किया जाये एवं पिलर बनने के उपरान्त सरिया दिखायी न दे, यह सुनिश्चित किया जाये। साथ ही जिलाधिकारी ने भवन के अन्दर निर्मित किये जा रहे शौचालय को भी देखते हुये आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित को दिये। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने पर्यटन विभाग द्वारा जनपद सीतापुर स्थित ग्राम रोजहा, पो0 धौरेमऊ, विकास खण्ड ऐलिया में प्राचानी शिव मंदिर में कराये जा रहे कार्यों को देखा। जिलाधिकारी ने इंटरलाकिंग, सोलर लाइट आदि कार्यों को देखते हुये प्रकाश व्यवस्था सही न मिलने पर संबंधित अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुये प्रकाश व्यवस्था सही करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कार्यों को पूर्ण करते हुये हैण्डओवर किया जाये।

प्रसिद्ध उत्तराखंडी गायक किशन महिपाल ने रोहिणी उत्तराखंड उत्सव में अपना जलवा बिखेरा

लोकतंत्र की शान, सुनील नेगी

उत्तराखंड उत्सव, रोहिणी ,के समापन समारोह में, दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंडियों के इस भव्य आयोजन को बड़ी सफलता मिली। भारत के अंतिम गांव बद्रीनाथ के पास स्थित माना गांव के प्रख्यात गढ़वाली गायक किशन महिपाल ने अपनी मधुर आवाज और मनमोहक धुनों से हजारों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कल के समारोह में वे वाकई 'मैन ऑफ द मैच' रहे, जिन्होंने अपनी ऊर्जा और उत्साह से सभी को अंत तक नाचने पर मजबूर कर दिया। युवा, लड़कियां, महिलाएं और यहां तक कि बुजुर्ग भी भरपूर आनंद उठा रहे थे। समापन दिवस पर अल्मोड़ा के सांसद और केंद्रीय परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री अजय Ajay Tamta मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने संगीतकारों, आयोजकों, गायकों और इस विशाल आयोजन का उत्कृष्ट संचालन करने वालों को पुरस्कार वितरित किए। दूसरे दिन, गढ़वाल उत्तराखंड की स्वराज कोकिला कल्पना चौहान और उनके बेटे, प्रसिद्ध गायक रोहित चौहान ने अपने मधुर गीतों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। संगीतकार समेत कई गायकों को मंत्री

Ajay Tamta द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इनमें गोविंद दिगारी, नीरज चुफाल, किशन महिपाल, चंद्र प्रकाश, प्रकाश रावत, माया उपाध्याय, दर्शन फरसवान, नवीन टोलिया, सीएमडी चौधरी एंटरप्राइजेज, हरीश जोशी, मन्नू जोशी, नवनीत भैंसोरा, स्वाति भट्ट, मीना भंडारी, संगीत निर्देशक रणजीत, खेम सिंह बिष्ट, एमडी बिष्ट प्रॉपर्टीज और कार्यकर्ता आदि शामिल थे। रविवार को हुए समापन समारोह में हजारों की भीड़ उमड़ी, विशेषकर पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं। उत्तराखंड के स्वादिष्ट organic व्यंजनों, हस्तशिल्प, मनमोहक हथकरघा उत्पादों, स्वेटर, शॉल, हर्बल दवाइयां, बाजरा, Mandwa, फल, जूस और अन्य कई वस्तुओं के लगभग 65 स्टॉल लगाए गए थे, जिनका अच्छा कारोबार हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री अजय Ajay Tamta द्वारा प्रसिद्ध मुंबई कौथिग टीम को उसके मुख्य आयोजक केशर सिंह बिष्ट सहित एक ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजकों अनिल पानु, Manoj भंडारी और संजय अग्रवाल आदि को भी सम्मानित किया गया। तीन दिवसीय यह आयोजन बेहद सफल रहा। रोहिणी, बाहरी दिल्ली, दिल्ली और एनसीआर में रहने वाली उत्तराखंड की आबादी बड़ी संख्या में यहां उमड़ी और सांस्कृतिक उत्सव का भरपूर आनंद उठाया। इस वर्ष उत्तरायिणी और उत्तराखंड से संबंधित ऐसे कार्यक्रम दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न स्थानों पर लगभग सौ जगहों पर पूरे धूमधाम से आयोजित किए गए।

गैरसैंण विधानसभा क्षेत्र भरारिसैन में कई फीट बर्फ गिरी है, जहां लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं और रील बनाने का आनंद ले रहे हैं

लोकतंत्र की शान , सुनील नेगी

समुद्र तल से 7,800 फीट की ऊंचाई पर निर्मित भव्य गैरसैंण विधानसभा और उसके परिसर में कई फीट भारी बर्फबारी हुई, जहां पर्यटक, स्थानीय लोग और कर्मचारी बर्फ पर वॉलीबॉल खेलते और वीडियो बनाते हुए आनंदित नजर आए। उत्कृष्ट स्थापत्य नींव वाली इस इमारत का निर्माण तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के आदेश पर कांग्रेस शासन के दौरान किया गया था, जिसके लिए शुरू में 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे और बाद में इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। उत्तराखंड की जनता की इस मांग को पूरा करने के लिए कुछ बजट पारित किए गए थे कि गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाया जाए। इस मांग को पूरा करवाने के लिए उत्तराखंड आंदोलन के दृढ़ कार्यकर्ता बाबा मोहन सिंह ने लगभग सौ दिनों की भूख हड़ताल करके अपना प्राण त्याग दिए, लेकिन सैकड़ों विरोध प्रदर्शनों और कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेताओं द्वारा गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के आश्वासनों के बावजूद इसे स्थायी राजधानी घोषित नहीं किया जा सका। हालांकि, पूर्व नौकरशाह अनिल रतूड़ी के नेतृत्व में एक नया व्यापक आंदोलन आकार ले रहा है। वे उत्तराखंड, देहरादून, दिल्ली आदि

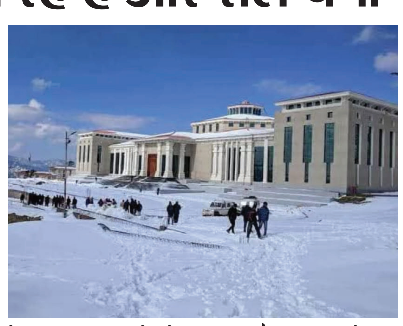

के विभिन्न हिस्सों में विशाल रैलियां आयोजित कर रहे हैं और गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को लामबंद कर रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने भी विपक्ष में रहते हुए इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। दोनों राष्ट्रीय दलों के नौकरशाह और यहां तक कि उत्तराखंड के नेता भी गैरसैंण जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि तीन हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित और गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य में होने के कारण भरारिसैन में कड़ाके की ठंड पड़ती है। उनके परिवार और बच्चे, जिनमें वे स्वयं भी शामिल हैं, वहां जाना मुश्किल होगा, क्योंकि वे देहरादून की राजधानी में काम करने के आदी हैं, जो सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण है। यह याद किया जा सकता है कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने की मांग उत्तराखंड क्रांति दल के घोषणापत्र में पहले दिन से ही शामिल थी, जब 1992 में अलग राज्य के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन में 43 बलिदान और अनगिनत विरोध प्रदर्शन, धरने, रैलियां शामिल थीं, जिनमें हजारों कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया, परेशान किया गया और उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों और दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों और देश के कई राज्यों में उन्हें प्रताड़ित किया गया। 9 नवंबर, 2000 को राज्य के गठन के बाद से, दोनों राष्ट्रीय दल मौखिक रूप से इस मांग को पूरा करने का आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन सत्ता में आने पर हमेशा मुकर गए हैं। हालांकि, कांग्रेस के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने विधानसभा भवन के निर्माण की पहल की और फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत और बाद में भाजपा सरकार द्वारा अपनाए गए ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्रों आदि की परंपरा का अनुसरण किया, ताकि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग कर रहे आंदोलनकारियों को दबाया जा सके। इसके बजाय, देहरादून में इसे जारी रखने के लिए एक नई समानांतर विधानसभा परियोजना भी चल रही है, जो उत्तराखंड की अधिकांश जनता को स्वीकार्य नहीं है।

भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने उप जिलाधिकारी हिमांशु उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार के नाम संबोधित करते हुए था जिसमें क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर समाधान की मांग की गई, संगठन के जिला अध्यक्ष हाजी हसीन अहमद गफारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग पर उत्पीड़न का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि बिजली बिल निकालने के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए, वहीं ईसापुर सरकी क्षेत्र में विद्युत् विभाग के जे ई पर किसानों के साथ अवधर व्यवहार करने और फोन न उठाने की शिकायत भी की गई, वहीं यूनियन ने थाना सैद नगली क्षेत्र के इलाका नंबर तीन में अवैध शराब के कारोबार और स्टाटर चोरी की घटनाओं पर चिंता व्यक्ति की, इसके अलावा भदौरा क्षेत्र में सिंचाई विभाग की पुलिया बनवाने और

राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज गर्ल्स हुआ में सड़क निर्माण की भी मांग उठाई, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने चेतावनी दी है कि यदि इन जनहित की समस्याओं को जल्दी समाधान नहीं किया गया तो संगठन उग्र आंदोलन को मजबूर होगा इस अवसर पर राजपाल सिंह चौहान, राजपाल सिंह, उस्मान चौधरी, जहीर अहमद सहित दर्जनों किसान नेता मौजूद रहे

बहुउद्देशीय सहकारी समिति भदौरा पर भारत टैक्सी की शुरुआत का लाइव प्रसारण देखा गया

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः गुरुवार को सहकार आधारित राइड बुकिंग सेवाओं के नए युग की शुरुआत के रूप में घेरे फ्री विकेंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा भारत टैक्सी योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के शुभारंभ के अवसर पर शाह ने योजना को भारत में सहकारी आधारित मोबिलिटी मॉडल को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्व पूर्ण पहल बताया। बहुउद्देशीय सहकारी समिति भदौरा पर कार्यक्रम को लाइव प्रसारण देखते समय उपस्थित सभापति कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि ड्राइवरों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए भारत टैक्सी एक ऐसा मंच लेकर आ रहा है जो ड्राइवरों को सशक्त बनाने का काम करेगा। इसके द्वारा उनको बेहतर कमाई पारदर्शी लाभ और बीमा जैसी सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जाएगा, इस अवसर पर उपसभापति समर पाल सिंह, सचिव सोनू कुमार,कंप्यूटर सहायक टिंकू कुमार, राम सिंह, महिपाल सिंह आदि मौजूद रहे।

वर्षों से मानदेय व रख-रखाव राशि न मिलने पर आक्रोषित सामुदायिक शौचालय केयर टेकरों का धरना

लोकतंत्र की शान , देवेंद्र सिंह

सीतापुर। विकासखंडों की ग्राम पंचायतों में संचालित सामुदायिक शौचालयों में कार्यरत केयर टेकरों को लंबे समय से मानदेय एवं शौचालय रख-रखाव के लिए शासन द्वारा निर्धारित 3000 प्रतिमाह की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे आक्रोशित केयर टेकरों ने सोमवार से धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना दे रहे केयर टेकरों का आरोप है कि कई ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान व सचिवों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के उन्हें कार्य से हटा दिया गया जो नियमों के विरुद्ध है। सकरन विकासखंड की ग्राम पंचायत टेड़वा कला की केयर टेकर रेखा देवी ने बताया कि उनका लगभग 31 माह का मानदेय बकाया है जबकि वे लगातार सेवाएं देती

रहीं। इसी तरह विकासखंड रेउसा की ग्राम पंचायत करसा की केयर टेकर सावित्री ने 57 माह से मानदेय लंबित होने की बात कही। अन्य केयर टेकरों ने भी कई-कई महीनों से भुगतान न होने का आरोप लगाया। केयर टेकरों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार ब्लॉक व पंचायत विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। धरना शुरू होने के एक दिन बाद भी न तो खंड विकास अधिकारी और न ही पंचायत विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचा। आरोप है कि केवल एलआईयू (लोकल इंटेलिजेंस यूनिट) के कर्मचारी धरना स्थल पर पहुंचे और फोटो लेकर चले गए लेकिन समस्याओं को सुनने या समाधान का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस संबंध में जनसमर्थ कल्याणकारी एसोसिएशन (रजि. 408015) द्वारा जिलाधिकारी सीतापुर को लिखित ज्ञापन भी सौंपा गया है जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया मानदेय 3000 प्रतिमाह रख-रखाव राशि के भुगतान तथा बिना नोटिस हटाए गए केयर टेकरों की पुनः बहाली की मांग की गई है। धरना दे रहे केयर टेकरों के संगठन जनसमर्थ कल्याणकारी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गुड्डू सिंह चौहान ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही सभी केयर टेकरों का बकाया भुगतान नहीं किया गया और हटाए गए कर्मचारियों को वापस कार्य पर नहीं रखा गया तो आंदोलन को जनपद स्तर से प्रदेश स्तर तक ले जाया जाएगा। इस पूरे प्रकरण ने पंचायत व्यवस्था स्वच्छ भारत मिशन और सामुदायिक शौचालयों की जमीनी सच्चाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

संक्षिप्त समाचार

नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, परिवार ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया

पटना। पटना के बेउर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। युवती की शादी दो महीने पहले ही धूमधाम से हुई थी। बुधवार को घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स भेज दिया है। मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस ने ससुराल के कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। युवती के पिता भोला राय ने बताया कि उनकी बेटी निशा कुमारी (20) की शादी 20 नवंबर 2025 को गर्दनीबाग निवासी संतोष कुमार (24) से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के समय उन्होंने दामाद को लगभग 8 लाख रुपये नकद, सोने की चेन और ढाई लाख रुपये से अधिक का सामान दिया था। इसके बावजूद, संतोष कुमार लगातार एक गाड़ी की मांग कर रहे थे। भोला राय ने आरोप लगाया कि बुधवार को उन्हें बेटी की मौत की सूचना मिली। जब वे ससुराल पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि निशा कुमारी की गला दबाकर हत्या की गई थी और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। फुलवारी शरीफ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी सुशील कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को बेउर थाना क्षेत्र के सिपारा बखानी मोहल्ले में एक नवविवाहिता द्वारा आत्महत्या करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया।

परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचे शिक्षक को नो एंट्री, लोग बोले- परीक्षार्थियों को जब प्रवेश नहीं तो टीचर को क्यों?

हाजीपुर। वैशाली के हाजीपुर स्थित सुखदेव मुखलाल कॉलेज के इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्र पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब परीक्षा के दौरान एक शिक्षक को निर्धारित समय से देर से पहुंचने पर केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने शिक्षक को केंद्र के गेट पर ही रोक लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार, संबंधित शिक्षक परीक्षा शुरू होने के लगभग 10 से 15 मिनट बाद परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे। जैसे ही वह अंदर जाने का प्रयास करने लगे, वहां मौजूद लोगों ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें प्रवेश से रोक दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षक और स्थानीय लोगों के बीच सवाल-जवाब होते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना था कि जब परीक्षार्थियों को एक मिनट की देरी पर भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाता और उनका पूरा साल खराब हो जाता है, तो परीक्षा संचालन से जुड़े शिक्षकों के लिए भी नियमों में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नियम सभी के लिए समान होने चाहिए और किसी को भी विशेष छूट नहीं दी जानी चाहिए। घटना के दौरान लोगों द्वारा बार-बार पूछे जाने के बावजूद शिक्षक ने अपना नाम और पहचान बताने से इनकार कर दिया। काफी देर तक चली बहस के बाद वह बिना प्रवेश किए ही मौके से लौट गए। इस घटना को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है और स्थानीय लोगों द्वारा नियमों के समान पालन की यह सख्त पहल सोशल मीडिया पर सराहना और बहस दोनों का विषय बनी हुई है।

5600 लीटर अंग्रेजी शराब-बीयर बरामद, ठेंगा डीह चंवर में छापेमारी, होली से पहले स्टॉक पर पुलिस का वार

हाजीपुर। वैशाली में जिले के करताहां थाना पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने थाना क्षेत्र के ठेंगा डीह गांव स्थित एक चंवर से लगभग 5600 लीटर अंग्रेजी शराब और बीयर जब्त की। बरामद शराब की कीमत का आकलन किया जा रहा है। विदित हो कि शराब कारोबार आगामी होली त्यौहार को देखते हुए शराब को बड़े पैमाने पर स्टॉक कर रहे थे। जिसके मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया है। शराब माफिया होली त्यौहार को लेकर बेहद सक्रिय है। लेकिन पुलिस और शराब कारोबारी के बीच चूहे बिल्ली जैसा खेल चल रहा है। मानो जैसे तुम डाल- डाल, मैं पात- पात की कहानी एकदम फिट बैठ रही है। करताहां थाना अध्यक्ष कुणाल कुमार आज़ाद ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि उक्त स्थान पर अवैध रूप से शराब छिपाकर रखी गई है। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि जब्त शराब को थाने लाया गया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। पुलिस शराब तस्करों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

मारपीट में घायल नौवीं के छात्र की मौत, वैशाली के डीह बिचौली गांव में बच्चों के विवाद के बाद हमला

हाजीपुर। वैशाली के महिसौर थाना क्षेत्र के डीह बिचौली गांव में मारपीट के बाद नौवीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। मृतक की पहचान 16 वर्षीय सुधीर कुमार के रूप में हुई है। सुधीर अपने पिता उदय महतो का इकलौता बेटा था। उसकी दो छोटी बहनें हैं। उदय महतो मजदूरी करते हैं। मृतक के चाचा बुधन कुमार ने बताया कि बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर पड़ोसी पवन महतो और उनके बेटे से झगड़ा हुआ था, जो बाद में शांत हो गया था। हालांकि, 30 जनवरी की सुबह जब सुधीर शौच के लिए घर से बाहर निकला और गांव में एक पुलिया पर बैठा था, तभी उसे लोहे की रॉड से पीटा गया।मारपीट के तुरंत बाद सुधीर बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर में भर्ती कराया। उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया गया। पटना के अस्पताल में डॉक्टरों ने ब्रेन के ऑपरेशन की बात कही, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत ऑपरेशन करवाया ।ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने फीस जमा करवा ली और परिजनों को बताया कि सुधीर की मौत हो गई है। इस संबंध में महिसौर थाना अध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि मारपीट में घायल किशोर की इलाज के दौरान मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया गया है। मारपीट मामले में 30 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

लापता किशोर का शव गंगा नदी से बरामद

पटना। पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रबाईच गांव निवासी किशोर अमित कुमार का शव गरुवार को गंगा नदी से बरामद किया गया। अमित पिछले चार दिनों से लापता था। जानकारी के अनुसार, अमित रविवार को अपने दोस्तों के साथ सबलपुर आया था। यहां सबलपुर के कुछ स्थानीय युवकों से उनका विवाद हो गया, जो जल्द ही झगड़े में बदल गया। झगड़े से बचने के लिए अमित और उसके दोस्त गंगा नदी की ओर भागे। आरोप है कि स्थानीय युवकों ने पीछा कर अमित और उसके दोस्तों को पकड़ लिया। इसके बाद नदी के पास उनके साथ मारपीट की गई। घटना की सूचना 112 नंबर पर दी गई। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही अमित को कथित तौर पर गंगा नदी में डुबो दिया गया। हालांकि, पुलिस ने गंगा किनारे से अमित के अन्य दोस्तों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद से नदी थाना की पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। ुरुवार को सबलपुर स्थित भुखमरिया भट्ठा के पास गंगा नदी के तट से अमित का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी प्रक्रिया पूरी की। नदी थाना के अपर थाना प्रभारी विवेक कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। घटना में शामिल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है।

इंटर एग्जामः वैशाली में छात्र की कॉलर से मिली चिट

एजेंसी, पटना

पटना-बगहा में चप्पल में पहुंचे स्टूडेंस

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा का आज गुरुवार को तीसरा दिन है। पहली पाली में फिजिक्स, जबकि दूसरी पाली में भूगोल (Geography) और बिजनेस स्टडीज की परीक्षा है। छात्रों को कड़ी जांच के बाद एंट्री दी गई। जूते बैन होने के कारण ठंड में स्टूडेंस चप्पल में एग्जाम देने पहुंचे। वैशाली में चेकिंग के दौरान एक छात्र के पास से चिट मिली। चीटिंग करते पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी। परीक्षा के लिए राज्यभर में 1,762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें कुल 13,17,846 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनमें 6,75,844 छात्राएं और 6,42,002 छात्र हैं। यह परीक्षा 13 फरवरी तक चलेगी।

अब तक 32 छात्र हो चुके हैं सस्पेंडः बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दो दिनों में अब तक कुल 32 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया जा चुका है। पहले दिन की परीक्षा में 26 परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में परीक्षा से बाहर किया गया। इसमें नवादा से सबसे अधिक 13 परीक्षार्थियों को बाहर किया गया। वहीं जहानाबाद और गोपालगंज से 3-3, मधेपुरा और भागलपुर से 2-2 परीक्षार्थियों को बाहर किया गया। इसके अलावा गया, अररिया और कटिहार से 1-1 परीक्षार्थी निष्कासित हुए। दूसरे दिन भी बोर्ड की सख्ती जारी रही। इस दौरान 6 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया, जिनमें नवादा से 3, रोहतास से 2 और सीवान से 1 परीक्षार्थी शामिल हैं।

100 अंक के पेपर में 50 सवाल ऑब्जेक्टिव होंगेः बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अनुसार, हर साल में 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव प्रश्नों में भी ऑप्शन दिए जाएंगे। उत्तर पुस्तिका और OMR शीट पर बारकोड भी रहेगा, जिससे जांच के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना न के बराबर होगी। सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र और OMR शीट समझने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। इस दौरान उत्तर लिखना शुरू नहीं करना है, केवल प्रश्नों को पढ़ने और समझने की अनुमति होगी।

नीट छात्रा रेप-मौत केस, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का लाइसेंस होगा कैंसिल

एजेंसी, पटना

❑ **डीजीपी विनय कुमार बोले- मैनेजमेंट ने की लापरवाही, उपमुख्यमंत्री ने जारी किए सख्त गाइडलाइंस**

पटना नीट छात्रा रेप-मौत केस में शंभू गर्ल्स हॉस्टल का लाइसेंस कैंसिल होगा। साथ ही हॉस्टल की संचालिका पटना में कोई भी हॉस्टल रन नहीं कर पाएंगी। बिहार डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि गर्ल्स हॉस्टल मैनेजमेंट से बड़ी लापरवाही हुई है इसलिए उनपर एक्शन लिया जाएगा। वहीं सीबीआई के केस टेकओवर से पहले एसआईटी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि परिजन केस दर्ज नहीं कराना चाहते थे। एसएसपी ने माना कि एक कपड़े पर स्पर्म मिला है। कदमकुआं के एसआई और चित्रगुप्तनगर थानेदार को निलंबित किया गया है। इधर, मृतका के परिजनों ने जांच पर सवाल उठाए। कहा कि एसआईटी लगातार बयान बदल रही है। सही जांच की बजाय परिवार पर आत्महत्या मानने का दबाव है। पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। परिजनों ने पूछा कि दवा से मौत हुई तो रेप किसने किया। दवा के पत्ते को उन्होंने पिता की दवा बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि केस पॉक्सो एक्ट में दर्ज है। सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। एसआईटी ने अब तक की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को दी है। 9 जनवरी को परिजनों के बयान पर केस दर्ज हुआ था। छात्रा की उम्र 18 साल से कम थी। सभी बयानों की वीडियोग्राफी कराई गई है। मीडिया के सवालों पर अधिकारियों ने नो कमेंट कहा। परिजनों ने पूछा- दवा से मौत हुई तो रेप किसने किया नीट छात्रा मामले में एसआईटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस और परिजनों के बयान आमने-सामने आ गए हैं। केस दर्ज करने से लेकर दवा, रेप और जांच तक हर मामले पर आरोप और जवाब टकरा रहे हैं।

बिहार के लड़के ने मुंबई में आत्महत्या की

एजेंसी, पटना

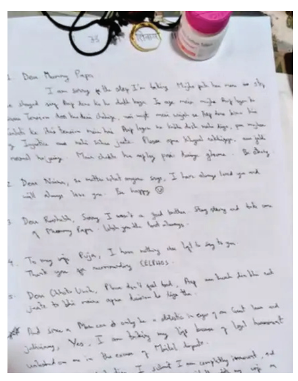

मोतिहारी के सौरभ ने 2 फरवरी को सल्फास खाकर मुंबई में आत्महत्या कर ली थी। मौके से सौरभ का एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने मां-पिता, पत्नी और अंकल के नाम का भी जिक्र किया है। सौरभ ने सुसाइड नोट में अपने परिवार से माफी मांगी है। यह घटना नवी मुंबई के न्यू पनवेल सेक्टर-7 स्थित कॉसमॉस को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की है। सौरभ मिश्रा मोतिहारी जिले के सुगौली के रहने वाले थे। वे मुंबई की एक निजी कंपनी में काम करते थे और अपने माता-पिता के साथ पनवेल में रह रहे थे। 2 फरवरी को माता-पिता घर पर मौजूद नहीं थे और सौरभ अकेले थे।

इसी दौरान उन्होंने कीटनाशक (सल्फास) खाकर आत्महत्या कर ली। सोमवार सुबह करीब 10 बजे जब माता-पिता घर लौटे तो उन्होंने सौरभ को बेहोशी की हालत में पाया। घबराहट में परिजन तुरंत उन्हें पनवेल उप-जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सौरभ को मृत घोषित कर दिया। प्रिय मम्मी-पापा, मैं जो कदम उठा रहा हूं, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। शायद आप दोनों ने कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन मैं कमजोर पड़ गया। इस उम्र में मुझे आप लोगों की सारी टेंशन दूर कर देनी चाहिए थी। मेरी वजह से आप दोनों बिना किसी गलती के इतनी परेशानी झेल रहे हैं। मुझसे यह अन्याय सहा नहीं जा रहा है। प्लीज अपना ख्याल रखिए और जल्दी सामान्य हो जाइएगा।

पीके की जन सुराज का आरोप, कहा- महिलाओं को 10 हजार देना भ्रष्ट आचरण, आज सुनवाई

एजेंसी, पटना

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द कर नए सिरे से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। जन सुराज पार्टी की ओर से दायर रिट याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमॉल्या बागची की पीठ करेगी।

आचार संहिता के दौरान महिलाओं को 10,000 रुपए देने का आरोपः याचिका में आरोप लगाया गया है कि आचार संहिता लागू रहने के बावजूद राज्य सरकार ने महिलाओं को सीधे 10 हजार रुपए दिए। जन सुराज का कहना है कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है। इसे भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। पार्टी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 112, 202 और 324 का उल्लंघन बताया है।

नए लाभार्थियों को जोड़ना और भुगतान को बताया अवैधः जन सुराज ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चुनाव अवधि में नए लाभार्थियों को जोड़ने और उन्हें भुगतान किए जाने पर भी आपत्ति जताई है। याचिका में कहा गया है कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान किसी भी नई योजना का विस्तार या भुगतान अवैध है।

निर्वाचन आयोग से कार्रवाई के निर्देश की मांगः पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (भ्रष्ट आचरण) के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि 25 से 35 लाख महिला मतदाताओं को सीधे वित्तीय लाभ देना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ है।

जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं की तैनाती पर आपत्तिः जन सुराज ने दोनों चरणों के मतदान के दौरान स्वयं सहायता समूह 'जीविका' से जुड़ी लगभग 1.8 लाख महिला लाभार्थियों की मतदान केंद्रों पर तैनाती को भी अवैध और अनुचित बताया है। पार्टी का दावा है कि इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हुई है।

मुफ्त योजनाओं पर दिशानिर्देश बनाने की मांगः याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य (2013) मामले में दिए गए निर्देशों की तरह मुफ्त योजनाओं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देश दे।

सैदपुर से गायघाट तक कवर्ड नाले का हो रहा निर्माण, रेलवे लाइन के नीचे से नाला बनाने के लिए एनओसी का इंतजार

एजेंसी, पटना

♦ **मानसून से पहले पूरा करने का लक्ष्य**

पटना में मानसून से पहले नालों के निर्माण में रफ्तार लाई जा रही है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) की ओर से इन नालों का निर्माण किया जा रहा है। सैदपुर से गायघाट तक कवर्ड नाला बनाया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 5.6 किलोमीटर है, जिसमें 3.3 किलोमीटर कवर्ड और 2.3 किलोमीटर खुला होगा। सैदपुर से 500 मीटर दूरी तक पश्चिम की ओर नाला को डायवर्ट किया गया है। इस दिशा से लगभग 16 मीटर नाला और दोनों ओर की ढलाई दीवार बनाई गई है। पहाड़ी की ओर से त्रिलोक नगर तक नाला निर्माण हो चुका है।

विभाग की ओर से नालों पर रोड निर्माण की मिली स्वीकृतिः बुडको एमडी अनिमेष कुमार पराशर ने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से पटना के अनकवर्ड नालों को कवर करके रोड निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसमें राजीव नगर और आनंदपुरी नाले में तेजी से काम चल रहा है। सैदपुर नाले का भी काम प्रगति पर है। वहीं, बाकरगंज नाले का निर्माण पटना स्मार्ट सिटी की ओर से किया जा रहा है। बुडको इसकी कार्यकारी एजेंसी है। मानसून से पहले अशोक राजपथ तक के लेन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

रेलवे लाइन के नीचे से नाला बनाने के लिए NOC का इंतजारः RMRI और NMCH के पीछे से होकर गायघाट तक सैदपुर नाला का निर्माण फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। पहाड़ी से लेकर त्रिलोक नगर तक बने नाला को उत्तर की ओर अगमकुआं रेलवे लाइन के समीप नीचे से निकालना है। रेलवे लाइन के नीचे से नाला बनाने के लिए रेल विभाग से अनुमति प्राप्त करने की विभागीय प्रक्रिया जारी है। नाला का भूतल नाव के आकार का 7 मीटर चौड़ा और 12 मीटर ऊंचा बनाया जा रहा है।

180.99 करोड़ रुपए में कुर्जी नाले का होगा निर्माणः कुर्जी नाले का निर्माण दीघा आशियाना रोड पर राजीव नगर ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन से कुर्जी ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन तक किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 4.26 किलोमीटर है। इस नाले पर सड़क निर्माण किया जाना है, जिसकी राशि 180.99 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इस नाला की संरचना बॉक्स ड्रेन होने की वजह से नाले के उपर निर्बाध यातायात के लिए फोर-लेन सड़क निर्माण के साथ-साथ स्ट्रीट लाइट को भी सम्मिलित किया गया है।

बगहा, मधुबनी में घना कोहरा, 12 जिलों में अलर्ट

एजेंसी, पटना

बगहा और मधुबनी में गुरुवार सुबह घना कोहरा है, विजिबिलिटी 20 मीटर है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में घना कोहरे का अलर्ट जारी किया है। सुबह और देर शाम धुंध के कारण विजिबिलिटी कम रह सकती है, जिससे वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल मौसम में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। सुबह और शाम कनकनी बनी रहेगी, जबकि दिन में धूप निकलने से ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बीते 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिला। इस दौरान विजिबिलिटी करीब 100 मीटर तक रही। वहीं, 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा। मौसम विभाग ने चेताया है कि बिहार समेत पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-4C की गिरावट हो सकती है। इससे ठंड का असर फिर से तेज होने की संभावना है, खास कर के रात और सुबह के समय। अगले दो दिनों तक बिहार के अलग-अलग इलाकों में सुबह और रात के समय घने कोहरे की संभावना है। दिन में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवा और नमी की मौजूदगी में उत्तर बिहार के जिलों में घना कोहरा छा रहा है। यही वजह है कि सुबह के समय विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर तक सिमट सकती है। वेदर एक्सपर्ट का कहना है कि फिलहाल कोई पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव नहीं है, इसलिए बारिश की संभावना नहीं है।

पटना-गयाजी पैसेंजर ट्रेन 21 मार्च तक रद्द

एजेंसी, पटना

गयाजी जंक्शन पर यात्रियों को भविष्य में बेहतर और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मेजर री-डेवलपमेंट का कार्य शुरू हो गया है। इस कार्य के तहत प्लेटफॉर्म संख्या-2 और 3 पर 5 फरवरी से 21 मार्च तक 45 दिनों का मेगा ब्लॉक लिया गया है। इस ब्लॉक अवधि के दौरान रेल परिचालन को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए कई ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किए गए हैं। रेल प्रशासन के अनुसार, कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्गों से चलाया जाएगा।

कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ भी किया गया है। ब्लॉक के कारण पटना-गयाजी-पटना पैसेंजर ट्रेन (53213/53214) को 5 फरवरी से 21 मार्च तक रद्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पटना-भभुआ रोड और भभुआ रोड-पटना इंटरसिटी, बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस, गंगा-दामोदर एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनें वैकल्पिक मार्गों से संचालित की जाएंगी। परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनों को आरा, सासाराम, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (डीडीयू), तिलैया, इस्लामपुर, फतुहा, पैमार और बंधुआ जैसे स्टेशनों से होकर गुजारा जाएगा। यह व्यवस्था गयाजी स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के प्रभाव को कम करने के लिए की गई है।

पटना नगर निगम बनाएगा जन-सुझावों से बजट

निगम कार्यालय में दे सकते अपनी राय, शहर के विकास से जुड़े मुद्दे शामिल होंगे

एजेंसी, पटना

पटना नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसको लेकर नगर निगम की ओर से आम नागरिकों से सुझाव मांगे गए थे, ताकि शहर के विकास से जुड़े मुद्दों को बजट में शामिल किया जा सके। पटना के नागरिक अपने सुझाव लिखित रूप में पटना नगर निगम कार्यालय में जमा करा जा सकते हैं। इसके अलावा ई-मेल या डाक से भी भेज सकते हैं। नागरिक pmclerkhasaction@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।

7 फरवरी को निगम बोर्ड की बैठकः दूसरी ओर 7 फरवरी को निगम बोर्ड की बैठक है। नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए अब म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करेगा। म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पटना नगर निगम राज्य का पहला नगर निकाय होगा। निगम ने एके कैपिटल को अपना मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया है। यह एजेंसी बॉन्ड की संरचना, नियामक अनुपालन, वित्तीय परामर्श, निवेशकों के साथ समन्वय और निर्गम से जुड़ी सभी तकनीकी और प्रक्रियागत आवश्यकताओं में निगम को सहयोग देगी।

निगम के आय-व्यय का आकलन होगाः म्युनिसिपल बांड जारी करने से पहले संबंधित नगर निकायों की वित्तीय स्थिति और आय-व्यय की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। राजस्व संरचना और ऋण चुकाने की क्षमता का भी स्वतंत्र मूल्यांकन होगा। सबकुछ बेहतर रहा तो इस दिशा में नगर निगम आगे बढ़ेगा। इससे पहले निगम बोर्ड की बैठक में इसको लेकर चर्चा होगी। बॉन्ड जारी करने के कई फायदे होंगे। नगर निगम को केंद्र या राज्य सरकार के अनुदान पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कामकाज में वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही बढ़ेगी।

बोर्ड बैठक कई एजेंडों पर चर्चा होगीः बोर्ड बैठक कई एजेंडों पर चर्चा होगी। इसमें डोर-टू-डोर कचरा उठाव के लिए वाहन और उपकरणों की खरीद, प्रत्येक वार्ड में 1-1 करोड़ रुपए की योजना, 14 उच्च क्षमता वाले बोरिंग लगाना, विज्ञापन संशोधन विनिमय 2025 का प्रारूप, बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन के लिए ब्याज और जुर्माना में छूट, पिछली कार्यवाही की संपुष्टि भी शामिल है।

ख़ास ख़बर

भारत अमेरिका समझौता को पूर्व मंत्री सीडब्ल्यूसी के सदस्य ने जताया विरोध,बोले विकास में डालेगा प्रतिकूल प्रभाव

रामबिहारी पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख लोकतंत्र की शान सीधी । भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विवरणों को लेकर कमलेश्वर पटेल ने गंभीर आपत्ति और चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह समझौता देश के किसानों, छोटे व्यापारियों और घरेलू उद्योगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और सरकार को इस पर देश के सामने स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

कमलेश्वर पटेल ने कहा कि उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार इस समझौते के तहत अमेरिकी उत्पाद शून्य शुल्क पर भारत में प्रवेश करेंगे, जिनमें सूखे मेवे, फल सब्जियां, मदिरा एवं स्पिरिट्स जैसे उत्पाद शामिल हैं। इसके साथ ही भारत द्वारा औद्योगिक वस्तुओं पर शुल्क को वर्तमान लगभग 13.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत भारत द्वारा अमेरिका से तेल, गैस और प्रोपेन जैसे ऊर्जा संसाधनों की खरीद बढ़ाने तथा लगभग 500 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी उत्पादों की खरीद का वचन देना भी सामने आया है, जिसमें कृषि उत्पाद शामिल बताए जा रहे हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद करेगा। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि इन प्रावधानों के बीच चिंताजनक तथ्य यह है कि भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में लगभग 18 प्रतिशत शुल्क लागू रहेगा। यदि यह स्थिति सही है, तो यह स्पष्ट असंतुलन को दर्शाती है जहां भारतीय बाजार खुल रहा है लेकिन भारतीय निर्यात को समान अवसर नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था भारतीय किसानों और व्यापारियों के लिए सीधा आघात बन सकती है क्योंकि सस्ते आयात घरेलू उत्पादन और बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेंगे, जबकि भारतीय उत्पादों पर बाहरी बाजार में बाधाएं बनी रहेंगी। कमलेश्वर पटेल ने केंद्र सरकार से प्रश्न किया कि यदि इस समझौते से देश के किसानों और व्यापारियों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, तो सरकार ने ऐसे प्रावधानों पर सहमति क्यों दी और किन परिस्थितियों में भारत के हितों को इस प्रकार जोखिम में डाला गया। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत गंभीर विषय है और इस समझौते का पूर्ण विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए तथा संसद में व्यापक चर्चा कराई जानी चाहिए ताकि देश को सच्चाई पता चल सके और राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

नगरपालिका क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करने पहुंची अध्यक्ष निर्माण एजेंसियों को दी दिशा निर्देश

लोकतंत्र की शान सीधी। नगर पालिका परिषद सीधी क्षेत्रान्तर्गत विविन्न वार्डों में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण अध्यक्ष श्रीमती काजल वर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान उनके साथ निकाय के उपयंत्री अकाश उदैनिया एवं अन्य तकनीकी कर्मचारी मौजूद रहे। नपा अध्यक्ष श्रीमती काजल वर्मा ने अपने निरीक्षण के दौरान नगर पालिका परिषद के वार्ड क्र 3,9,10 एवं 11 में चल रहे नाली निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता एवं समय सीमा में पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये। भ्रमण के दौरान अध्यक्ष ने आमजन मानस कि समस्या भी सुनी गई एवं तत्काल विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को निरकराण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

नूंह में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव,परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

लोकतंत्र की शान :नूंह। नूंह जिले के पिनगवां थाना क्षेत्र के गांव पापड़ी के जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शोयब के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष बताई जा रही है। पिनगवां थाना क्षेत्र के गांव रहपुआ का निवासी है। गुरुवार सुबह किसान जब जंगल की ओर फसल देखने गए तो उन्होंने पेड़ से लटका शव देखा। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए बताया कि शोयब रात करीब 12 बजे तक घर में ही मौजूद था। इसके बाद वह कैसे जंगल तक पहुंचा, यह सवाल खड़े करता है। परिजनों का कहना है कि युवक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। टैंकर चालक शोयब आसपास के गांवों में पानी सप्लाई का काम करता है। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। शव जंगल में मिलने के बाद पूरे मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सूचना मिलते ही पिनगवां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अल आफिया अस्पताल मांडीखेड़ा भेज दिया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों और सच्चाई का खुलासा हो सकेगा। घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव और चर्चा का माहौल बना हुआ है।

सिरसा: शिक्षा और स्वास्थ्य पर घटता खर्च हरियाणा के भविष्य के साथ अन्याय: सैलजा

लोकतंत्र की शान : सिरसा। सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हाल ही में आई रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आया है कि हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत क्षेत्रों पर प्रति व्यक्ति खर्च राष्ट्रीय औसत से कम है। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि यही दो क्षेत्र किसी भी राज्य के मानवीय विकास, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की नींव होते हैं। सांसद सैलजा ने गुरुवार को मीडियो को जारी प्रेस बयान में कहा कि राज्य सरकार बड़े-बड़े दावे करती रही है कि नए मेडिकल कॉलेज, बेहतर अस्पताल, आधुनिक विद्यालय और महाविद्यालय खोले गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर अलग दिखाई देती है। अनेक सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, दवाइयां और जांच सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकारी व्यवस्थाएं कमजोर होती हैं तो आम नागरिक को मजबूरन निजी संस्थानों की ओर रुख करना पड़ता है, जिससे शिक्षा और चिकित्सा का बोझ परिवारों पर बढ़ता है। यह स्थिति विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कठिनाई पैदा करती है। सैलजा ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में ठोस वृद्धि करे, रिक्त पदों को शीघ्र भरे, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए, और इन सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करे। उन्होंने यह भी कहा कि घोषणाओं से अधिक ज़रूरत है प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता की, ताकि जनता को वास्तविक लाभ मिल सके। कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा के बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों का अधिकार है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिले।

बुजुर्ग से पैसा ऐंठने वाले गिरोह के तीन आरोपी गिरफतार

» लिफ्ट देने के बहाने उड़ा लिया था 50हजार

लोकतंत्र की शान रामबिहारी पाण्डेय ब्यूरो

सीधी। स्थानीय सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में लुटेरे एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं बैंकों से निकलने वाले बुजुर्ग जनों को अपना निशाना बना रहे हैं कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह को बेनकाब किया है साथ ही उनसे तेरह लाख की सामग्री तप्त किया है। पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह को पकडऩे में सफलता हासिल की है, जो राहगीरों को मदद के बहाने गाड़ी में बैठाकर पलक झपकते ही उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर देते थे। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अभिषेक उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर ली है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता लालबहादुर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3 फरवरी 2026 को बैंक से 50,000 रुपये निकालकर जाते समय बोलेरो सवार बदमाशों ने उन्हें बस स्टैंड छोडऩे का झांसा देकर बैठाया। रास्ते में आरोपियों ने दरवाजा ठीक से बंद नहीं है का बहाना बनाया और गेट बंद करने के बहाने बुजुर्ग को बातों में उलझाकर बड़ी सफाई से नोट भरे बैग की चेन खोलकर 50,000 रुपये चोरी कर लिए और कुछ दूर आगे उन्हें बोलेरो से नीचे उतारकर फरार हो गए। पुलिस जांच में यह गंभीर तथ्य सामने आया है कि पकड़े गए आरोपी आदतन अपराधी हैं। इन अपराधियों के विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न जिलों के अलग-अलग थानों में चोरी, लूट और झपटमारी के कई मामले दर्ज हैं। यह गिरोह रेकी कर बैंक से निकलने वाले अधिक उम्र के बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाता था और रास्ते में झांसा देकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। आरोपियों में देवेन्द्र उर्फ लाला यादव 26 वर्ष निवासी बाणगंगा रीवा, सुधीश यादव 21 वर्ष निवासी बाणगंगा रीवा, दुर्गेश शर्मा 32 वर्ष निवासी रामगढ़ जिला मैहर आदि से 33 हजार रुपए नकद एवं चोरी के पैसों से खरीदा गया 14 हजार रुपए का मोबाइल, घटना में प्रयुक्त सफेद बोलेरो कीमती 12 लाख, कुल मशरूका लगभग 12.47 लाख रुपये जप्त किया गया। इस गिरोह को बेनकाब करने में थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक उपाध्याय, उनि विवेक द्विवेदी, उनि राजमणि अहिरवार, सउनि विनोद त्रिपाठी, प्रआर रणबहादुर सिंह, प्रआर तिलकराज सिंह, प्रआर जितेन्द्र पाठक, प्रआर आनंद शर्मा और आरक्षक अनुराग यादव व प्रखर पाण्डेय की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। इनका कहना है।

कलेक्टर श्री तिवारी के निर्देश पर लगातार कार्यवाही जारी

बरही में रेत के उत्खनन में संलिप्त दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी। कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक में खनिज के अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्यवाही करने के दिए निर्देश के पालन में खनिज अमले द्वारा सतत् कार्रवाई का सिलसिला जारी है।

बडवारा में आयोजित जनसुनवाई में शामिल होने पहुंचे विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को कलेक्टर श्री तिवारी ने निर्देशित किया था कि, जनसुनवाई के बाद सभी अधिकारी अपने- अपने विभागों की मैदानी स्तर पर क्रियान्वित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निरीक्षण करें। हितग्राहियों से मिलें, निर्माण एवं विकास से संबंधित विभाग इन कार्यों को देखने पहुंचें। कलेक्टर के इसी निर्देश पर अमल करते हुए खनिज अमले द्वारा मंगलवार को कटनी-बडबारा रोड पर खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की गई । जांच में सभी वाहनों में वैध दस्तावेज पाए गए। इसके अलावा सूचना प्राप्त होने पर ग्राम पिपरिया बहिरघटा के पास नदी घाटों का निरीक्षण किया गया। जिसमें दो ट्रैक्टर ट्रॉली बिना दस्तावेज के नदी में रेत भरते पाए गए ।जिन्हें जप्त कर प्रकरण तैयार किया गया ।जिसमें आगामी कार्यवाही के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा।.इस कार्यवाही में उपसंचालक खनिज श्री रत्नेश दीक्षित और खनिज निरीक्षक बरही उपस्थित रहे।

धान खरीदी केंद्रों के भ्रष्टाचार की पोल रहे अधिकारियों के पत्र

» क्रासर; रामपुर नैकिन शाखा प्रबंधक के पत्र ने खोले खरीदी में की गई झोल की पोल
» धनहा समिति का हैं मामला
» सर्रा कैंप प्रभारी की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल

लोकतंत्र की शान रामबिहारी पाण्डेय ब्यूरो

सीधी। जिले के धान खरीदी केंद्रों में समिति प्रबंधकों द्वारा की गई धांधली की पोल खुलने लगी है, खटिया किस्म की धान को गोदामों में पहुंचाने के लिए समिति प्रबंधक पुर जोर कोशिश में लगे हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण रामपुर नैकिन शाखा प्रबंधक का पत्र है, जिसमें शाखा प्रबंधक रामपुर नैकिन ने यह साफ उल्लेख किया है कि सेवा सहकारी समिति संस्था समिति धनहा में खराब धान एवं बदरा आदि भर कर भेजा गया है, शाखा प्रबंधक के अनुसार धनहा समिति की चार टीसी निरस्त करने योग्य है, उन्होंने ने जिला प्रबंधक नान को लिखे पत्र में यह साफ उल्लेख किया है कि धनहा समिति की चार टीसी एवं सर्रा कैंप के दो स्टैको की जांच आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन शाखा रामपुर नैकिन के शाखा प्रबंधक ने 30 जनवरी को उक्त के संबंध में पत्र लिखा है, उन्होंने अपने पत्र में यह साफ उल्लेख किया है कि धनहा समिति की चार टीसी निरस्त कर जांच कराया जाना आवश्यक है, इसके अलावा शाखा प्रबंधक ने सर्रा कैंप की गड़बड़ियों को भी अपने पत्र में उजागर किया है।

सर्रा कैंप प्रभारी पर पहले भी हो चुकी हैं कार्यवाही

बता दें कि सर्रा कैंप प्रभारी पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लग चुके हैं, उनके खिलाफ विभाग द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर कार्यवाही भी की जा चुकी हैं लेकिन अब भी वह अपने क्रियाकलापों में बदलाव नहीं ला रहे हैं। सूत्रों के अनुसार घटिया धान का भंडारण जहां धड़ल्ले से किया जा रहा है वहीं वजन पूरा करने के लिए बोरियों अखाद्य सामग्री भी डाली जा रही है। इतना ही नहीं अगर किसी के द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों से की जाती हैं तो उसे झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी भी दी जाती है।

यह है शाखा प्रबंधक का पत्र

म०प्र० वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन शाखा कार्यालय - रामपुर नैकिन, जिला सीधी के पत्र क्रमांक /मप्रवेलाका / 2025-26/110 दिनांक 30-01-2026 के अनुसार उन्होंने जिला प्रबंधक म०प्र० स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो० सीधी को पत्र लिखकर सेवा सहकारी संस्था समिति धनहा की धान की चार टीसी को रिजेक्ट करने एवं सर्रा कैप दो स्टैको की जॉच करने के मांग उठाई है। पत्र के अनुसार शाखा रामपुर नैकिन अंतर्गत सर्रा कैप में धान 2025 -26 का भण्डारण किया जा रहा है जिसमें सेवा सहकारी संस्था समिति धनहा के द्वारा खराब धान एवं बदरा आदि भर कर भेजा गया है। जो जमा कराने योग्य नहीं है, जिसकी जांच कर कार्यवाही की मांग की गई है। बता दें कि शाखा प्रबंधक के पत्र से सर्रा कैंप प्रभारी एवं धनहा समिति प्रबंधक पर कार्यवाही होना तय माना जा रहा है।

चार टीसी को निरस्त करने की मांग

शाखा प्रबंधक रामपुर नैकिन द्वारा लिखें गए पत्र में इस बात का साफ उल्लेख किया गया है कि सर्रा कैंप में धनहा समिति द्वारा भेजी जा रही धान में खराब धान एवं बदरा भर कर भेजा जा रहा है। शाखा प्रबंधक के अनुसार टीसी क्रमांक 593151170162, 593151170169, 593151170170, एवं टीसी क्रमांक 593151170171 की धान खराब है, जिसे समिति प्रबंधक धनहा द्वारा सर्रा कैंप प्रभारी की साठगांठ से जमा कर दिया गया है, हालांकि शाखा प्रबंधक रामपुर नैकिन के पत्र से जांच शुरू कर दी गई है।

आधा दर्जन समितियों में हैं गोलमाल

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार जिले के आधा दर्जन समितियों में धनहा समिति की तरह गोलमाल किया गया है, जिला प्रबंधक नान मांगीलाल बड़ेरा द्वारा निरंतर भ्रमण कर ऐसी समितियों को चिन्हित किया जा रहा है, जल्द ही अन्य समितियों के फर्जीवाड़े की सच्चाई भी सामने आएगी। जानकारी अनुसार जिले में धान खरीदी के दौरान ही भ्रष्टाचार में लिप्त समिति प्रबंधकों द्वारा व्यापारियों से सेटिंग जमाकर सड़ी गली धान क्रय कर ली थी, अब उसी धान को अच्छी धान के साथ खपाने में जुटे हैं।

फर्जी मार्कशीट से पेट्रोलपंप लेने पर मामला दर्ज

लोकतंत्र कि शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

फर्जी व कूट रचित मार्कशीट के आधार पर सुभांशु नगरिया निवासी डन कॉलोनी, मदन मोहन चौबे वार्ड, कटनी को रीठी में गोपाल फिलिंग के नाम से पेट्रोल पंप लेना मंहगा पड़ गया है । फरियादी सुनील सेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मिथलेश जैन ने न्यायालय को बतलाया कि आरोपी द्वारा फर्जी व कूट रचित मार्कशीट तैयार कर तथा उसे भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड में देकर पेट्रोल पंप प्राप्त करने का गंभीर अपराध किया है, उनके तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, कटनी के द्वारा सुभांशु नगरिया के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 467, 468 एवं 471 का मामला पंजीबद्ध करने का आदेश जारी किया गया है । विदित है कि रीठी में पेट्रोल पंप आवंटित किये जाने हेतु भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2015 में आवेदन मंगवाये थे जिसमें आरोपी सुभांशु नगरिया ने अपने आवेदन पत्र के साथ तमिलनाडू विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण करने की एक मार्कशीट लगाई थी । इन दस्तावेजों के आधार पर उसे पेट्रोल पंप आवंटित कर दिया गया,

जिसे कि उसके द्वारा गोपाल फिलिंग के नाम से संचालित किया जाने लगा । समाज सेवी एवं आर.टी. आई. एक्टिवीस्ट सुनील सेन को उक्त जानकारी मिलने पर उनके द्वारा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड में शिकायत की गई । शिकायत पर जॉच होने के उपरांत भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने शिकायत को सही पाकर व मार्कशीट फर्जी होना पाकर पेट्रोल पंप का आवंटन निरस्त कर दिया । सुनील सेन द्वारा इससंबंध में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु पुलिस को शिकायत की थी लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने शिकायतकर्ता सुनील सेन एवं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक जबलपुर की साक्ष्य लेने व दस्तावेजों को देखने के उपरांत सुभांशु नगरिया के विरुद्ध धारा 467, 468, 471 भा.द.सं. का अपराधा् पंजीबद्ध किया गया है ।

वन अमले के संरक्षण में हो रहा रेत का उत्खनन परिवहन

» मझौली डिप्टी रेंजर व रेत माफिया के सांठ गांठ की खुली पोल
» गश्ती दल ने पकड़े अवैध रेत से भरे दो ट्रैक्टर

लोकतंत्र की शान

सीधी। वन परिक्षेत्र मझौली अंतर्गत वृत्त चमराडोल में पदस्थ परिक्षेत्र सहायक जीएन सिंह चौहान व रेत माफिया के बीच लंबे समय से सांठ–गांठ की गश्ती दल ने रेत से भरे बगैर दस्तावेज के ट्रैक्टर व सहयोग में एक बोलेरो वाहन एवं एक मोटरसाइकिल को जप्त कर कलई खोल कर रख दी। वन परिक्षेत्र मझौली अंतर्गत चमराडोल वृत्त अंतर्गत लंबे समय से रेत उत्खनन व परिवहन परिक्षेत्र सहायक के सांठ गांठ से किए जाने की क्षेत्र में व्यापक चर्चाएं थी जिसमें गश्ती दल द्वारा दिनांक 5 फरवरी 2026 को वन परिक्षेत्र अधिकारी सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में बीट चमराडोल के कक्ष क्रमांक आर 13 11 (आर 490) वन खंड मड़वास पाठ की वन सीमा पड़वारी नाला से वनोपज रेत का अवैध उत्खनन एवं चोरी कर वाहन ट्रैक्टर आईसर वाहन क्रमांक एमपी 53 जेड बी 5436 बगैर दस्तावेज/टी पी अवैध परिवहन के दौरान वाहन की नाकाबंदी कर सीधी से व्योहारी मुख्य मार्ग दड़ौर पहुंच मार्ग पर जप्त कर वैधानिक कार्यवाही की गई।मौके से ही वाहन बोलोरो क्रमांक एमपी 18डी 0982 के साथ एक मोटरसाइकिल

क्रमांक एम पी 18 एम एस 1188 को वन अपराध के सहयोग में संलिप्प पाए जाने पर जप्त किया गया एवं मौके की कार्यवाही पूर्ण कर अपराध क्रमांक 72/16 दिनांक 05.02. 2026 दर्ज किया गया। इसी प्रकार उक्त जप्ती कार्यवाही उपरांत 5 फरवरी को ही रात्रि गश्ती के दौरान मझौली से मड़वास मुख्य मार्ग पर ग्राम खड़ौरा में वनोपज रेत से भरे बिना किसी वैध दस्तावेज के परिवहन करते हुए ट्रैक्टर महिंद्रा वाहन क्रमांक एम पी 18 एबी 1454 को भी जप्ती की कार्यवाही कर उपवन मंडल अधिकारी मझौली को वाहनों को राजसात करने की कार्यवाही की जाकर वन अपराध क्रमांक 93/12 दिनांक 05.02.2026 पंजीबद्ध किया गया। घटनास्थल के पास ही बीट मझौली के कक्ष क्रमांक आर 1331(आर491) वनखंड चोरवा स्थिति है।अभियुक्त वाहन मालिक के विरुद्ध पूर्व में भी वनोपज परिवहन में संलिप्तता पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की गई थी। परिक्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में की गई ताबड़तोड़ कार्यवाही से जहां एक ओर परिक्षेत्र सहायक जीएन सिंह के इमानदारी की सारी कलई खुल गई है वहीं दूसरी ओर रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।

वन चौकी के बगल से निकल रही थी रेत

रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन को लेकर समाचार पत्रों में खबर प्रकाशन कर वन विभाग की निष्क्रियता पर सवाल उठाया गया था क्योंकि जिस वन सीमा की जगहों से रेत निकाला जाता है ठीक बगल में विभाग की चौकी व जिम्मेवारों के रहने के लिए कमरे बनाए गए इसके बाद भी बड़े पैमाने पर रेत का कारोबार फल फूल रहा है।

महिलाओं को सशक्तिकरण एवं स्वावलंबी बनाने वाला बजट : रीती पाठक

» बजट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प : प्रज्ञा त्रिपाठी
» बजट पर महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित

लोकतंत्र की शान रामबिहारी पाण्डेय ब्यूरो

सीधी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रतिपूर्ति के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया। बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन के लिए लाखों-लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना, लखपति दीदी, स्टार्टअप, स्व सहायता समूह और अनेकता नेक सौगाते दी गई है। उक्त आशय के विचार भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित केंद्रीय बजट पर महिला संवाद कार्यक्रम भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता एवं केंद्रीय बजट महिला मोर्चा आयोजन समिति की संयोजक और मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की सदस्य प्रज्ञा त्रिपाठी की विशिष्ट उपस्थिति में संबोधित करते हुए सीधी विधायक श्रीमती रीती पाठक ने कही। महिला संवाद के दौरान विधायक श्रीमती रीती पाठक ने कहा कि देश की आधी आबादी अर्थात महिलाओं के सशक्तिकरण से भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। बजट को लेकर महिला संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रीवा भाजपा की वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य प्रज्ञा त्रिपाठी ने बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पाथेय साबित होगा। पेश किए गए बजट में महिलाओं के लिए वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण, प्रत्येक जिला केन्द्र पर महिला खिलाड़ियों के लिए सर्व सुविधा युक्त एवं आधुनिक स्टेडियम का निर्माण, स्व सहायता समूह द्वारा संचालित और ग्रामीणों द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं के लिए जिला केन्द्र पर बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल, स्व रोजगार के लिए हजारों करोड़ लाखों का प्रावधान, 18 विभागों के माध्यम से उद्यमी बनाना, जीवन रक्षक दवाइयां जैसे कैंसर, किडनी व अन्य प्रकार की बीमारियों के लिए 70 प्रतिशत तक की छूट की व्यवस्था करना प्रमुख रूप से शामिल है। महिला सशक्तिकरण से हमारा देश विश्व का मार्गदर्शन करेगा। समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारी बहनें बराबर की सहभागी बने। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कृत संकल्पित है। मुख्य वक्ता श्रीमती त्रिपाठी ने बजट को लेकर महिलाओं से विस्तृत और व्यापक संवाद किया।

अध्यक्षीय उद्बोधन में भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पेश किया गया बजट सर्व स्पर्शी एवं सर्वव्यापी है। किसान, युवा, महिला सभी के लिए पर्याप्त राष्ट्र आवंटित किया गया है। केंद्रीय बजट की खूबियों को लेकर जिले भर में प्रदेश एवं केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। महिला संवाद में अभियान के संयोजक विश्व बंधुधर द्विवेदी एवं महिला मोर्चा की अध्यक्ष पूनम सोनी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष अंजू केसरी, जिला उपाध्यक्ष डॉ अशोक पटेल, मनीला सिंह चौहान, बजट टोली के सदस्य उमाशंकर यादव, सुरेंद्र मणि दुबे, जितेंद्र तिवारी, मंडल अध्यक्ष पंकज पाण्डेय, नीलम पाण्डेय, सुनीता रानी वर्मा, आशा शुक्ला, विभा शर्मा, ज्योति कुशवाहा, कंचन केसरी, संगीता सिंह चौहान, जगदंबा सोनी, अन्नू पाण्डेय, पार्षद शुभा देवी कोल, ओमता सोनी, संगीता सिंह चौहान, महिमा तिवारी, ज्योति कनौजिया, ममता सोनी, महिमा तिवारी, सरिता सोनी, सुधा नामदेव, सविता सोनी, सरोज शर्मा, पूजा कोल, यशोदा रावत, सोनिया, चंद्रकली शिवानी कोल, शालिनी कोल, निशा नामदेव, रेनू त्रिपाठी सहित अनेक महिलाए उपस्थित रही।

संक्षिप्त समाचार

अमेरिकी अखबार में छंटनी-शशि थरूर के बेटे की नौकरी गई

वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने बुधवार को 800 पत्रकारों में से 300 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। इसमें सीनियर कॉलमिस्ट ईशान थरूर भी शामिल हैं। वे कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे हैं। ईशान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वॉशिंगटन पोस्ट ने इंटरनेशनल टीम के कई शानदार पत्रकारों के साथ

उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया है। यह न्यूज रूम के लिए बेहद दुखद दिन है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मैट मरे ने बताया कि जेफ बेजोस की कंपनी पिछले कई सालों से घाटे में चल रही थी। इस छंटनी में स्पोर्ट्स सेक्शन पूरी तरह बंद कर दिया गया है, हालांकि कुछ रिपोर्टर फीचर्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट होकर स्पोर्ट्स की कल्चर कवरेज जारी रखेंगे। लोकल न्यूज सेक्शन छोटा हो जाएगा, बुक्स सेक्शन बंद हो जाएगा और डेली न्यूज पॉडकास्ट 'पोस्ट रिपोर्ट्स' भी खत्म हो जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने मिडिल ईस्ट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से भी रिपोर्टर और एडिटर निकाल दिए हैं।

संसदीय समिति बोली-रेलवे आरएसी बर्थ मिलने पर आंशिक किराया लौटाए

नई दिल्ली। संसदीय समिति ने मंगलवार को कहा RAC कैटेगरी के तहत बुक किए गए टिकटों के लिए यात्री से पूरा किराया लेना सही नहीं है। समिति ने रेल मंत्रालय को सुझाव दिया कि रेल मंत्रालय को ऐसे यात्री को आंशिक किराया वापस करने के लिए नियम बनाना चाहिए। मौजूदा नियम के तहत, रेलवे RAC कैटेगरी के तहत ट्रेनों में बर्थ बुक करने के लिए यात्री से पूरा किराया लेता है। हालांकि, यात्री RAC कैटेगरी में रह सकता है और बर्थ दूसरे RAC यात्री के साथ साझा

कर सकता है। दोनों यात्री रेलवे को पूरा किराया देते हैं। वहीं, सुपरफास्ट ट्रेनों को कैटेगराइज करने के लिए समिति ने कहा कि इसके लिए 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार का बेंचमार्क बेहद कम है। समिति ने कहा कि 2007 से सुपरफास्ट ट्रेनों के कैटेगराइजेशन के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी 55 किमी/घंटे की रफ्तार वाली ट्रेनें सुपरफास्ट मानी जाती हैं। लेख लेखा समिति(PAC) ने बुधवार को संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट 'भारतीय रेलवे में ट्रेन संचालन में समय की पाबंदी और यात्रा का समय' में कहा कि RAC (कैंसलेशन के बदले आरक्षण) के तहत टिकटों के लिए पूरा किराया लेना सही नहीं है। इसमें चार्ट बनने के बाद भी टिकट धारक को बिना बर्थ की सुविधा के RAC कैटेगरी में रहना पड़ता है। समिति ने रेलवे से ऐसे यात्रियों को आंशिक किराया वापस करने और इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में उसे सूचित करने का आग्रह किया।

एमपी के 30 और यूपी के 15 जिलों में कोहरा

नई दिल्ली/लखनऊ/देहरादून/शिमला। देश के उत्तरी राज्य अगले 5 दिन में एक बार फिर दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रभावित होंगे। पहला डिस्टरबेंस 5-6 फरवरी को एक्टिव रहेगा। इसके चलते मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा, यूपी के 15 जिले, पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़, उत्तराखंड में सुबह कोहरा छाया रहा। कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी रुक गई है। लेकिन तापमान लगातार माइनस में दर्ज किया जा रहा है। उत्तराखंड में पाला पड़ा है। पाला ऐसी कंडीशन है, जब रात में तापमान बहुत गिर जाता है और हवा की नमी जमकर पौधों, घास या जमीन पर बर्फ जैसी

सफेद परत बन जाती है। वहीं राज्य में बद्रीनाथ में माइनस 20 तापमान रिकॉर्ड हुआ है। हिमाचल प्रदेश का कुकुमसेरी में माइनस 12.2° के साथ सबसे सर्द इलाका बना हुआ है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में अभी बर्फीली हवाओं से तापमान में गिरावट हो रही है। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में धीरे-धीरे दिन और रात का तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक 9-10 फरवरी को एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा जिससे पश्चिमी हिमालय में कुछ जगहों पर बारिश/बर्फबारी की आशंका है।

भोपाल में छात्राओं पर कटर से हमला

भोपाल। भोपाल में तीन छात्राओं पर कटर से हमला करने वाले साइको मैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे बुधवार रात छोला इलाके में घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी का नाम देवेंद्र अहिरवार है। वह सागर जिले का रहने वाला है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पत्नी से झगड़ा होने के बाद उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बाद एक तीन छात्राओं को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर 20 हजार रुपए इनाम था। क्राइम ब्रांच, अयोध्या नगर और पिपलानी थाने की 5 टीमें उसकी तलाश में लगी थी। इसमें करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। इसके लिए पुलिस ने शहर के आपराधिक प्रवृत्ति वालों का डेटा निकालकर भी मैच करने

की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक,आरोपी शराब पीने का आदी है और भोपाल में मजदूरी करता है। पुलिस ने बदमाश की तलाश के लिए 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए। इसके बाद उसे बदमाश का सुराग लगा। सिरफिरे देवेंद्र अहिरवार ने 29 जनवरी की रात पत्नी से विवाद किया था। इसके बाद बाइक पर सवार होकर निकला। भानपुर ब्रिज के रास्ते आरोपी अयोध्या नगर और पिपलानी इलाके में पहुंचा। यहां उसने तीन छात्राओं पर कटर से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दो छात्राओं को गंभीर चोटें आई थीं, जबकि एक को मामूली चोट लगी। 30 जनवरी को पीड़िताओं की शिकायत पर अयोध्या और पिपलानी पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी। आरोपी अलग-अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ था। आरोपी ने अपना चेहरा रूमाल से ढंक रखा था। पिपलानी इलाके में ही आरोपी ने एक अन्य युवती पर भी हमला किया था। हालांकि मामूली रूप से घायल हुई थी।

'20 हजार के लिए बेटी मार डाली'

कैथल। कैथल में 3 दिन पहले दहेज के लिए हुई महिला ज्योति की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। ज्योति के पिता ने कहा कि 20 हजार रुपए के लिए पति ने उसे मार डाला। ज्योति पर बार-बार पैसे लाने का दबाव बनाया जा रहा था। वह उसे कह रहे थे कि उनकी कपड़े की दुकान में लॉस हो गया है, इसलिए पैसे लेकर आ। इसी बात पर 2 फरवरी को ज्योति के पति ने लकड़ी की फट्टी से उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसमें उसकी मौत हो गई। पिता का कहना है कि दहेज को लेकर काफी लंबे

समय से बेटी को परेशान किया जा रहा था। पूंडरी थाने में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ज्योति के पति को गिरफ्तार कर चुकी है। 2017 में हुई थी शादीः ज्योति के पिता वेद प्रकाश ने बताया कि 4 मार्च 2017 को बेटी की शादी डूलियाणी गांव के सुरजीत के साथ की थी। सुरजीत प्लंबर का काम करता है। शादी के बाद 7 साल का बेटा दक्ष और 5 साल की बेटी दीक्षा है। पिछले 5 साल से सुरजीत अपने परिवार से अलग रह रहा है।

रूस बोला-भारत किसी से भी तेल खरीदने के लिए आजाद

एजेंसी, मॉस्को

◻ **इसमें कुछ भी गलत नहीं, भारत ने तेल खरीद रोकने की आधिकारिक जानकारी नहीं दी**

रूस ने बुधवार को कहा कि भारत किसी भी देश से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पूरी तरह आजाद है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस कभी भी भारत का एकमात्र एनर्जी पार्टनर नहीं रहा है। अगर भारत तेल की खरीद किसी और देश से करता है, तो इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। पेस्कोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है, इस तरह की कोई भी ऑफिशियल जानकारी भारत की ओर से नहीं दी गई है। उन्होंने एक दिन पहले भी यही बात कही थी कि नई दिल्ली से ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है।

ट्रम्प का दावा- भारत रूसी तेल खरीदना बंद करेगाः इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोमवार को कहा था कि भारत, अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के तहत रूस से तेल खरीद रोकने को तैयार हो गया है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है। इसके तहत भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है। उन्होंने दावा किया कि इसके बदले में भारत, रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और व्यापार से जुड़ी टैरिफ की रुकावटें भी कम करेगा।

रूसी प्रवक्ता बोलीं- तेल खरीदी दोनों देशों के लिए फायदेमंदः रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने बुधवार को रूस और भारत के बीच हाइड्रोकार्बन व्यापार जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा भारत की रूसी हाइड्रोकार्बन की खरीद दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। यह वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। हम अपने भारतीय साझेदारों के साथ निकट सहयोग जारी रखने के लिए तैयार हैं। इस बीच रूस के एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के लिए रूसी तेल को पूरी तरह छोड़कर किसी और देश का तेल लेना आसान नहीं है। नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी फंड के विशेषज्ञ इगोर युशकोव ने बताया कि अमेरिका जो तेल बेचता है, वह हल्का होता है, जबकि रूस, भारत को भारी और सल्फर वाला यूराल्स क्रूड सप्लाई करता है जिसका इस्तेमाल भारतीय रिफाइनरियां करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत अमेरिका से हल्का तेल खरीदेगा, तो उसे दूसरे तेलों के साथ ब्लेंड (मिक्स) करना पड़ेगा, ताकि मशीनें ठीक से चल सकें। ऐसा करने पर भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी। यानी कि भारत को अमेरिकी तेल खरीदना ज्यादा महंगा पड़ेगा।

लुंबिनी में 29-30 अप्रैल को तीसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होगा

एजेंसी, काठमांडू

लुंबिनी में 29-30 अप्रैल को तीसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को हुई लुंबिनी विकास कोष की परिषद बैठक ने लुंबिनी के पर्यटन प्रवर्द्धन और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में लुंबिनी के प्रचार-प्रसार को नई ऊंचाई तक ले जाने के लक्ष्य के साथ इस सम्मेलन के आयोजन का निर्णय लिया। संस्कृति, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री तथा लुंबिनी विकास कोष के अध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक ने अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के लिए मूल आयोजक समारोह समिति के गठन को भी मंजूरी दी। लुंबिनी विकास कोष के उपाध्यक्ष डॉ. ल्हारक्याल लामा को संयोजक बनाते हुए 10 सदस्यीय मूल समारोह समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने चालू आर्थिक वर्ष के लिए सम्मेलन आयोजन के लिए 3 करोड़ रुपये का बजट विनियोजित किया है। इससे पहले देश में हुए राजनीतिक और संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण नवंबर में प्रस्तावित सम्मेलन को 2570वीं बुद्ध जयंती के अवसर पर आगामी 29-30 अप्रैल को लुंबिनी में आयोजित करने की तैयारी की गई है। समारोह समिति के संयोजक डॉ. लामा ने बताया कि बुद्ध धर्म और दर्शन के माध्यम से विश्व शांति को बढ़ावा देने, दया, करुणा और विश्व बंधुत्व की भावना फैलाने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में विश्व के 60 से अधिक देशों से बौद्ध विद्वानों, गुरुओं, विशिष्ट अतिथियों तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तित्वों की भागीदारी रहने की उम्मीद है। दो दिवसीय सम्मेलन में बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी, कपिलवस्तु तथा बुद्ध से जुड़े क्षेत्रों की धरोहर, लुंबिनी क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति, विश्व बौद्ध धरोहर, बौद्ध शिक्षा और संस्कृति जैसे विषयों पर चर्चा और कार्यपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।

तमिलनाडु के मिनिस्टर बोले-उत्तर भारतीय यहां पानीपुरी बेचते हैं

♦ **उन्हें सिर्फ हिंदी आती है, हमारे बच्चे तमिल-अंग्रेजी जानते हैं, विदेश में करोड़ों कमा रहे**

एजेंसी, नई दिल्ली

तमिलनाडु के कृषि मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने कहा कि उत्तर भारत से आए लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिलतीं। वे तमिलनाडु आकर टेबल साफ करने, मजदूरी करने या पानी पूरी बेचने जैसे काम करते हैं। पन्नीरसेल्वम ने बुधवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की दो-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) की वजह से हमारे बच्चे अमेरिका, लंदन जैसी जगहों पर जाकर करोड़ों कमा रहे हैं। बीजेपी और दूसरी विपक्षी पार्टी DMK नेता के इस बयान का विरोध कर रहे है।

तमिलनाडु बीजेपी ने सोशल मीडिया X पर पन्नीरसेल्वम की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह केवल एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक पैटर्न बन चुका है। भाजपा ने कहा- DMK के कई नेता प्रवासी मजदूरों का, विशेषकर उत्तर भारतीय या हिंदी बोलने वालों का बार-बार मजाक उड़ा चुके हैं। ऐसे में जब तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, इस तरह के बयान गैर-जिम्मेदाराना और खतरनाक हैं।

चुनाव नज़दीक आते ही ओली पर दबाव बढ़ा रणनीतिक गठबंधनों की चर्चा फिर तेज

एजेंसी, काठमांडू

अगले माह 5 मार्च को होने वाले चुनाव में अब समय कम रह गया है जिससे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएन-यूएमएल) पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सितंबर में हुए जेन-जी आंदोलन के बाद पैदा हुआ राजनीतिक असर अब चुनावी परिदृश्य को स्पष्ट रूप से प्रभावित करने लगा है। पिछले साल 8 और 9 सितंबर को हुए जेन-जी प्रदर्शनों के दौरान हुई मानवीय और भौतिक क्षति को लेकर यूएमएल लगातार आलोचना के घेरे में है। उस समय पार्टी अध्यक्ष और तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। आलोचकों का आरोप है कि ओली ने हिंसा की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की और यही आरोप पार्टी का पीछा करता रहा है। हाल ही में ओली ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जान गंवाने वाले 19 लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की लेकिन इससे जनआक्रोश शांत नहीं हो सका। ज्यादातर प्रमुख दलों के स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के फैसले के बीच यूएमएल की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। काठमांडू महानगर के पूर्व मेयर बालेन शाह का झापा-5 से चुनाव लड़ने का निर्णय ओली पर अतिरिक्त दबाव बना रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र परंपरागत रूप से उनका गढ़ माना जाता रहा है। वहीं, यूएमएल के महासचिव शंकर पोखरेल भी दांग-2 में कड़े मुकाबले का सामना कर रहे हैं, जिससे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर खतरे की आशंका बढ़ गई है। इसी पृष्ठभूमि में ओली ने कुछ चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में सीमित चुनावी सहयोग की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन थापा द्वारा किसी भी प्रकार के गठबंधन को स्पष्ट रूप से नकारे जाने के बाद, ओली कथित तौर पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) के साथ समन्वय की संभावनाएं टटोल रहे हैं। उधर, एनसीपी के समन्वयक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचंड' पर भी राजनीतिक दबाव दिखने लगा है। उन्होंने हाल ही में एक भावुक वीडियो संदेश जारी कर संकेत दिया कि वे प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में नहीं हैं और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। यूएमएल–एनसीपी संभावित समन्वय की अटकलों को तब और बल मिला जब अंतरिम सरकार ने देशभर में 80 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात कर यह स्पष्ट कर दिया कि 5 मार्च के चुनाव स्थगित नहीं होंगे। ऐसे में ओली और प्रचंड दोनों ही अपने-अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश में जुटे नजर आ रहे हैं। ओली जहां झापा में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, वहीं प्रचंड रुकुम पूर्व में अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस करने के बावजूद देशव्यापी बेहतर नतीजों के रास्ते तलाश रहे हैं। ओली एनसीपी या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) के साथ गठबंधन के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। 2022 के चुनावों में यूएमएल और आरपीपी के बीच सफल समन्वय देखने को मिला था, जिसमें ओली ने झापा-5 और आरपीपी अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन ने झापा-3 से जीत हासिल की थी। हालांकि, लिंगदेन ने संकेत दिया है कि आरपीपी इस बार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, जिससे ओली का रुझान एनसीपी की ओर बढ़ता दिख रहा है। एनसीपी नेताओं ने पुष्टि की है कि ओली ने चुनावी सहयोग का प्रस्ताव रखा है, हालांकि अभी तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं हुआ है।

स्पीकर बोले-कल पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैंने लोकसभा में उनकी स्पीच टाली

एजेंसी, नई दिल्ली

दावा- कांग्रेस ने हमले की प्लानिंग की थी

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। इसलिए उनकी कल शाम 5 बजे होने वाली स्पीच टालनी पड़ी। आशंका के चलते मैंने ही उनसे न आने का आग्रह किया था। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बुधवार को PM की स्पीच के दौरान कांग्रेस लोकसभा में उन पर हमला करने की योजना बना रही थी, इसी आशंका के चलते स्पीकर ने सदन स्थगित करने का फैसला लिया। दरअसल, पीएम मोदी 5 फरवरी को लोकसभा में शाम 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों के हंगामे के चलते स्पीकर संध्या राय ने कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित कर दी। इससे पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन भी टल गया था। वहीं, धन्यवाद प्रस्ताव को हंगामे के बीच गुरुवार पास कराया गया। 2004 के बाद पहली बार यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना पास हुआ है।

स्पीकर बोले- पोस्टर लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगाः लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा- कल लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में जो हुआ, वह सदन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब सदन के नेता पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। बिरला ने विपक्षी सांसदों से कहा कि आप पोस्टर लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा।

जिस तरह से महिला सदस्य पीएम की सीट तक पहुंची, उसे देश ने देखा। ये उचित नहीं था। ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। इस बीच विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे, इसको देखते हुए स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी।

मणिपुर की नई डिप्टी सीएम नेमचा किपगेन का विरोध

कुकी ग्रुप्स ने बंद बुलाया, आज से विधानसभा का सत्र शुरू होगा

एजेंसी, नई दिल्ली/इंफाल

मणिपुर में आज से विधानसभा का नया सत्र शुरू हो रहा है। यह सत्र नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद बुलाया गया है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने गुरुवार शाम 4 बजे से सत्र बुलाया है। इधर, दिल्ली में बुधवार शाम को कुकी-जो समूह से जुड़े लोगों ने मणिपुर भवन के बाहर प्रदर्शन किया। मणिपुर में जॉइंट फोरम ऑफ सेवन (JF7) ने शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कुकी बहुल इलाकों में बंद का आह्वान किया है। ये विरोध प्रदर्शन कुकी समुदाय से आने वाली उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन का किया जा रहा है। कुकी-जो परिषद ने कहा है कि यदि समुदाय का कोई विधायक सामूहिक फैसले के खिलाफ सरकार में शामिल होता है, तो उसके फैसले की जिम्मेदारी संगठन की नहीं होगी। नेमचा किपगेन कांगपोकपी से भाजपा विधायक हैं और इससे पहले बीरेन सिंह सरकार में सामाजिक कल्याण, सहकारिता, वाणिज्य, उद्योग और वस्त्र विभाग की मंत्री रह चुकी हैं।

आसाराम के अहमदाबाद आश्रम पर चलेगा बुलडोजर

♦ **हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमीन वापस लेने का आदेश दिया, 500 करोड़ से ज्यादा है कीमत**

एजेंसी, अहमदाबाद

अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित आसाराम का मुख्य आश्रम अब कानूनी विवादों में है। गुजरात हाईकोर्ट ने 45,000 वर्ग मीटर से अधिक की आश्रम की जमीन को राज्य सरकार के कब्जे में लेने और अवैध ढांचों को हटाने की मंजूरी दे दी है। इस आश्रम की जगह अब 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। वर्तमान में इस जमीन की मार्केट वैल्यू 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस वैभवी नानावती ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को जमीन वापस लेने की अनुमति दी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विकास परियोजना की आवश्यकता और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए सरकारी कार्रवाई उचित है.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 31 घंटे बाद जाम खुला, टैंकर पलटने से रास्ता बंद था

एजेंसी, मुंबई/पुणे

♦ **गाड़ियों की 25 किलोमीटर लंबी कतारें, डेढ़ लाख से ज्यादा लोग फंसे थे**

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर करीब 31 घंटे बाद गुरुवार सुबह ट्रैफिक जाम खुल गया। यहां 3 फरवरी से डेढ़ लाख वाहनों में लोग फंसे थे। गाड़ियों की 25 किमी लंबी कतारें लग गई थीं। जाम में फंसे लोगों को खाना, पानी और टॉयलेट सुविधाओं की कमी के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस जाम में फंसे लोगों में उद्योगपति और पिनैकल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुधीर मेहता भी शामिल थे। वे एक्सप्रेसवे पर लगभग आठ घंटे तक फंसे रहे और बाद में उन्हें हेलिकॉप्टर से पुणे ले जाया गया। मेहता ने बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हेलिकॉप्टर से ली गई जाम की तस्वीर शेयर की। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला घाट सेक्शन में 3 फरवरी की शाम करीब 5 बजे अडोशी टनल के पास एक गैस टैंकर पलट गया था। टैंकर से प्रोपाइलीन गैस लीक हो रही थी। इसके बाद सुरक्षा कारणों से एक्सप्रेसवे के कई हिस्से बंद करने पड़े थे। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MSRDC) के अनुसार, टैंकर में मौजूद प्रोपाइलीन गैस को दूसरे टैंकरों में ट्रांसफर किया गया। फिर क्षतिग्रस्त टैंकर को रास्ते से हटाया गया। तब जाकर जाम धीरे-धीरे खुलना शुरू हुआ। गैस लीक के बाद हालात संभालने के लिए NDRF, SDRF और भारत पेट्रोलियम (BPCL) की टीमें मौके पर तैनात की गई थीं। पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पूरी तरह बंद कर दी गई थी और ट्रैफिक को पुराने मुंबई-पुणे हाईवे की ओर डायवर्ट किया गया था। स्थिति को कुछ हद तक संभालने के लिए पुणे लेन से मुंबई की ओर 15–20 मिनट के ब्लॉक में गाड़ियां जा रही थी।

डिजिटल युग में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 के ऐतिहासिक नियम परिवर्तन -एक समग्र विश्लेषण

लोकतंत्र की शान

» भारत की प्रशासनिक भर्ती प्रणाली में एक ऐतिहासिक संरचनात्मक सुधार- यूपीएससी ने आईएएस-आईपीएस के लिए बदले नियम,अब बार-बार नहीं दे पाएंगे परीक्षा

» आईएएस और आईएफएस को स्टेपिंग स्टोन की तरह प्रयोग करने व अपग्रेड सिंड्रोम प्रवृत्ति पर सीधा प्रहार -सीरियल अटेम्प्ट संस्कृति पर निर्णायक प्रहार सराहनीय कदम -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर वर्तमान डिजिटल युग में जहां एक ओर तकनीक ने ज्ञान,सूचना और अवसरों को वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक बनाया है,वहीं दूसरी ओर इसी तकनीक के दुरुपयोग ने परीक्षा प्रणालियों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न भी खड़े कर दिए हैं। बीते कुछ वर्षों में भारत ही नहीं,बल्कि विश्व के अनेक देशों में उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, डिजिटल हैकिंग,प्रॉक्सी कैंडिडेट्स कोचिंग-माफिया गठजोड़ और मेरिट के क्षरण जैसी घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।भारत में नीट,रेलवे, राज्य लोक सेवा आयोगों और विभिन्न भर्ती बोर्डों की परीक्षाओं में सामने आए हैं मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि घोटालों ने यह स्पष्ट कर दिया कि पारंपरिक नियमों और ढांचागत कमजोरियों के साथ आधुनिक डिजिटल चुनौतियों का सामना करना अब संभव नहीं रह गया है। इसी पृष्ठभूमि में संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए जो नोटिफिकेशन 4 फरवरी 2026 को जारी किया है, वह केवल एक सामान्य भर्ती विज्ञापन नहीं,बल्कि भारत की प्रशासनिक भर्ती प्रणाली में एक ऐतिहासिक संरचनात्मक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। यह नोटिफिकेशन न केवल उम्मीदवारों के लिए नियमों में भारी परिवर्तन करता है, बल्कि यह स्पष्ट संकेत भी देता है कि आयोग अब मेरिट,अवसरों की समानता,नैतिकता और सेवा-प्रतिबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगा।यूपीएससी सीएसई -2026 के माध्यम से कुल 933 पदों पर भर्ती की जानी है,जिनमें से 33 पद बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 फरवरी 2026 से प्रारंभ हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हालांकि,इस बार आवेदन भरना मात्र औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि नए नियमों की जटिलता और दीर्घकालिक प्रभाव को समझे बिना किया गया कोई भी निर्णय उम्मीदवार के पूरे करियर को प्रभावित कर सकता है। साथियों बात अगर हम केवल एक अतिरिक्त मौकाः सीरियल अटेम्प्ट' संस्कृति पर निर्णायक प्रहार इस बदले हुए नियम को समझने की करें तो, नोटिफिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रावधान यह है कि जो आईएएस आईएफएस उम्मीदवार सीएसई -2025 या उससे पहले की परीक्षा के आधार पर किसी भी सिविल सेवा में चयनित या नियुक्त हो चुके हैं,उन्हें सीएसई-2026 या सीएसई -2027 में केवल एक बार और परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा।यह अवसर भी केवल उनके बचे हुए अटेम्प्ट्स के उपयोग तक सीमित रहेगा और इसके लिए उन्हें तत्काल सेवा से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होगी।यह नियम उस प्रवृत्ति पर सीधा प्रहार है जिसमें उम्मीदवार एक सेवा प्राप्त करने के बाद भी बार-बार परीक्षा देकर "अपग्रेड सिंड्रोम" का शिकार बने रहते थे। इससे न केवल नए और पहली बार प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के अवसर सीमित होते थे,बल्कि प्रशासनिक ढांचे में भी अस्थिरता उत्पन्न होती थी।नए नियमों के अनुसार, जो उम्मीदवार पिछली परीक्षाओं के परिणामस्वरूप भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो चुके हैं और वर्तमान में उन सेवाओं के सदस्य हैं, वे सीएसई -2026 में शामिल होने के लिए पूर्णतः अयोग्य होंगे।यह निर्णय वैश्विक प्रशासनिक प्रणालियों के अनुरूप है, जहां शीर्ष सेवाओं को एक करियर-फाइनल डेस्टिनेशन माना जाता है, न कि अस्थायी पड़ाव।इस प्रावधान का उद्देश्य स्पष्ट हैआईएएस और आईएफएस को एक बार प्राप्त करने के बाद उसे "स्टेपिंग स्टोन" की तरह प्रयोग करने की मानसिकता कोसटीक रूप से समाप्त करना। साथियों बात अगर हम प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद भी मेन्स का अवसर नहींः समय-आधारित निष्पक्षता इसको समझने की करें तो,यदि कोई उम्मीदवार सीएसई -2026 की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसे पिछली परीक्षा के आधार पर आईएएस या आईएफएस में नियुक्ति मिल जाती है और वह उस सेवा का सदस्य बना रहता है, तो वह सीएसई -2026 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने का पात्र नहीं रहेगा। यह नियम परीक्षा प्रक्रिया में टाइम-लाइन आधारित निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है और "दो नावों में पैर रखने" की प्रवृत्ति को रोकता है।यदि कोई उम्मीदवार मुख्य परीक्षा शुरू होने के बाद लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले आईएएस या आईएफएस में नियुक्त हो जाता है और सेवा में बना रहता है, तो उसे सीएसए -2026 के परिणाम के आधार पर किसी भी सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा।यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी उम्मीदवार एक ही समय में दो अलग-अलग चयन प्रक्रियाओं का लाभ न उठा सके। साथियों बात अगर हम हम आईपीएस के लिए 'नो री- एंट्री' नीति को समझने की करें तो नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि जो उम्मीदवार पिछली परीक्षा के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में चयनित या नियुक्त हो चुके हैं, वे सीएसई -2026 के परिणाम के आधार पर पुनः आईपीएस चुनने या उसमें शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। यह नियम पुलिस नेतृत्व में निरंतरता, प्रशिक्षण निवेश की सुरक्षा और प्रशासनिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।ट्रेनिंग से केवल एक बार छूटः सेवा- प्रतिबद्धता का नया मानक- आईएएस,आईपीएस या किसी अन्य ग्रुप-A सेवा में चयनित उम्मीदवार सीएसई - 2027 में तभी शामिल हो सकते हैं जब उन्हें सीएसई -2026 के आधार पर अलॉट की गई सेवा की ट्रेनिंग से केवल एक बार छूट दी गई हो। यह प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि प्रशिक्षण अब औपचारिकता नहीं, बल्कि सेवा का अनिवार्य और सम्मानजनक हिस्सा है। साथियों बात अगर हम 'नो स्टेप-नो सर्विस': फाउंडेशन कोर्स की अनिवार्यता को समझने की करें तो,नए नियमों के अनुसार, चयनित उम्मीदवार को फाउंडेशन कोर्स में शामिल होना अनिवार्य है। यदि कोई उम्मीदवार न तो ट्रेनिंग में शामिल होता है और न ही विधिवत छूट प्राप्त करता है,तो उसकी सेवा आवंटन स्वतःरद्द कर दीजाएगी। यह प्रावधान प्रशासनिक अनुशासन और संस्थागत संस्कृति को मजबूत करता है। यदि कोई उम्मीदवार सीएसई -2027 में चयनित होता है, तो वह या तो सीएसई -2026 या सीएसई -2027 में अलॉट की गई सेवा में से एक का ही चयन कर सकता है। चयनित सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी सेवा आवंटन स्वतः रद्द कर दिए जाएंगे। यह नियम उम्मीदवारों को स्पष्ट और जिम्मेदार निर्णय लेने के लिए बाध्य करता है।दोनों चयन रद्द होने की स्थितिः अंतिम चेतावनी- यदि उम्मीदवार न तो सीएसई -2026 और न ही सीएसई -2027 के आधार पर आवंटित सेवा की ट्रेनिंग में शामिल होता है, तो दोनों सेवाओं का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। यह प्रावधान यह दर्शाता है कि यूपीएससी अब अनिश्चितता और अनिर्णय को सहन करने के मूड में नहीं है।तीसरे प्रयास से पहले इस्तीफा अनिवार्यः करियर-फाइनलिटी की अवधारणा- नोटिफिकेशन का सबसे निर्णायक नियम यह है कि जो उम्मीदवार पहले दो प्रयासों में चयनित हो चुके हैं, वे तीसरी बार परीक्षा नहीं दे सकते। यदि वे सीएसई -2028 या उसके बाद किसी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें वर्तमान सेवा से इस्तीफा देना होगा। यह नियम सिविल सेवा को एक पूर्णकालिक प्रतिबद्ध करियर के रूप में स्थापित करता है। अतःअगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि भारतीय प्रशासनिक प्रणाली का नया युग यूपीएससी सीएसई -2026 का यह नोटिफिकेशन केवल नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि भारतीय प्रशासनिक भर्ती प्रणाली के नैतिक पुनर्गठन का दस्तावेज है। यह डिजिटल युग की चुनौतियों,अवसरों की समानता,प्रशिक्षण निवेश, सेवा- गरिमा और युवा प्रतिभाओं के लिए न्यायसंगत मंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक साहसिक कदम है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यह सुधार भारत को उन देशों की श्रेणी में खड़ा करता है जहां सिविल सेवा को केवल नौकरी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्तरदायित्व माना जाता है।जो उम्मीदवार 24 फरवरी 2026 तक आवेदन करने जा रहे हैं,उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे इस नोटिफिकेशन को केवल पढ़ें नहीं, बल्कि समझें, विश्लेषण करें और दीर्घकालिक रणनीति के साथ निर्णय लें, क्योंकि अब यूपीएससी में सफलता केवल परीक्षा पास करने का नाम नहीं, बल्कि स्पष्ट दृष्टि, नैतिक प्रतिबद्धता और सेवा-समर्पण की परीक्षा भी बन चुकी है।

-संकलनकर्ता लेखक-कर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
9226229318

"कविता के ख़रगोश"

लोकतंत्र की शान, -डॉ.जया शुक्ला

जितने चुपचाप दिख रहे हैं,
उतने हम हैं नहीं !!
शोर ही मचाना होता तो,
बूँद-हीन बादल बन जाते
कुछ सीमित बुद्धिजीवियोंकी,
मीठी फुहार मैं नहाते।
ऊँची दूकान चमचमाकर,
कहते वह लोग, बिक रहे हैं।
करते श्रम हैं नहीं !!
आज सवेरे हमने देखा,
बंजर सपना थमा थमा सा।
काले सागर मैं गिरता है,
भोला कोई ख़रगोश गीत का
कहकहे किनारे हैं, होंगे,
ज्वारों के बीच टिक रहे हम !
कोई भ्रम है नहीं !!
प्यार की जो आँच दिलों मैं थी,
चिंगारियों मैं बदलती है,
ख़रगोशों के दिलों मैं आख़िर,
गर्म हवाएँ उमड़ रही हैं।
हिमपातों की सुखद सी छवियाँ
दूर से हमें दिखा रहे हैं।
यह तो उपक्रम नहीं !!

सोशल मीडियाः संवाद का माध्यम या निजता का संकट?

सुनील कुमार महला

आज संचार क्रांति का युग है।हर कोई सोशल मीडिया,एआइ का प्रयोग कर रहा है। आधुनिक दौर में सोशल मीडिया ने हमारे अनेक कार्यों को आसान और सरल बनाया है। दूसरे शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया ने संवाद को जितना सरल और व्यापक बनाया है, उतना ही जटिल निजता का प्रश्न भी खड़ा कर दिया है। आज व्यक्ति अपने जीवन के निजी क्षण-तस्वीरें,रील बनाकर अपने विचार, स्थान और दिनचर्या स्वेच्छा से सार्वजनिक मंचों पर साझा कर रहा है। यह सब आमतौर पर सोशल मीडिया मंचों पर साझा करना कभी-कभी आत्म-अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, तो कई बार अनजाने में अपनी निजता को जोखिम में डालने का कारण बन जाता है। 'लाइक' और 'व्यू' की होड़ में निजी सीमाएँ धुंधली होती जा रही हैं। यहां यदि हम सरल शब्दों में कहें तो आज के समय में तकनीक हमारी ज़िंदगी की पल-पल की अहम् व महत्वपूर्ण जरूरत बन चुकी है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने काम आसान और तेज़ कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा है-निजता का खतरा। आज के समय में अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन है और वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि ऐप या प्लेटफॉर्म पर साइन-अप करते समय जो निजी जानकारी वे देते हैं, उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कई बार यह जानकारी हमारी अनुमति के बिना किसी और को दी जा सकती है। बहरहाल,यहां पाठकों को बताता चलूं कि भारत ही नहीं आज संपूर्ण विश्व स्तर पर स्मार्टफोन उपयोग तेजी से सर्वव्यापी हो चुका है। 2025 के आसपास उपलब्ध ताज़ा वैश्विक अनुमानों के अनुसार दुनिया में लगभग 6.8–7.1अरब लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, जबकि सक्रिय स्मार्टफोन डिवाइसों की संख्या 7 अरब से अधिक मानी जाती है, क्योंकि कई उपयोगकर्ताओं के पास एक से अधिक फोन हैं। इसका अर्थ यह है कि वैश्विक आबादी का करीब 85–90 प्रतिशत हिस्सा किसी न किसी रूप में स्मार्टफोन से जुड़ चुका है। यदि हम यहां पर भारत की बात करें तो देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन चुका है।साल 2024–2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 65–70 करोड़ (650–700 मिलियन) है, जो कुल जनसंख्या का करीब 45–50 प्रतिशत बैठती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और 4जी/5जी नेटवर्क के विस्तार के कारण यह संख्या तेजी से बढ़ रही है और विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार 2026 तक भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ता 100 करोड़ के आसपास पहुँच सकते हैं । इस क्रम में यहां यह गौरतलब है कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सऐप को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी कंपनी नागरिकों की निजी जानकारी के साथ मनमानी नहीं कर सकती और निजता के अधिकार से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज का जमाना डिजिटल है और इस डिजिटल युग में आज मोबाइल नंबर, बैंक खाता, आधार जैसी जगहों पर हमें अपनी निजी और कभी-कभी बायोमेट्रिक जानकारी भी देनी पड़ती है।

सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर

लेखक-हर्षवर्धन पान्डे

लता की मखमली और जादुई आवाज की दुनिया दीवानी थी। उनकी आवाज़ दिल को छूती नहीं, बल्कि दिल में बस जाती थी। हर दिल अजीज लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से हिंदी सिनेमा की गायकी में ऐसे चार चाँद लगाए कि हर कोई उनका मुरीद हुए बिना नहीं रह पाया। सही मायनों में हिंदी सिनेमा की गायकी की दुनिया को लता ने अपने मधुर स्वर से नई दिशा देने का काम किया। लता दीदी की वो आवाज हर किसी के दिल के तारों को आज भी झंकृत कर देती है। हिंदी सिनेमा के 100 बरस से अधिक के सफ़र में लता दीदी की गायकी सिल्वर स्क्रीन पर चार चाँद लगा देती है। एक ऐसी आवाज हिन्दी फ़िल्म संगीत में हमेशा के लिए अमर रहेगी। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। लता पांच भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। लता मंगेशकर का जन्म के वक्त नाम हेमा रखा गया था लेकिन कुछ साल बाद अपने थिएटर के एक पात्र लतिका के नाम पर, दीनानाथ जी ने उनका नाम लता रखा। लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थे। लता की तीन बहनें मीना, आशा, उषा और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर थे। पांच साल की उम्र में ही लता जी ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी और थिएटर में एक्टिंग किया करती थी। जब वो स्कूल गयी तो वहां के बच्चों को संगीत सिखाने लगी लेकिन जब लता जी को अपनी बहन आशा को स्कूल लाने से मना किया गया तो उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया।सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर का भी बॉलीवुड में सफर इतना आसान नहीं था। काफी समय तक उन्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। प्रोजेक्ट नहीं मिलने की दो वजहें थीं। एक तो साल 1940 के दौर में जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में एंट्री ली बॉलीवुड में नूर जहां और शमशाद का दबादबा था और दूसरा लता की आवाज़ की पिच काफी हाई थी और आवाज़ पतली, ऐसे में उस दौर के चलन में चल रहे गानों के मुताबिक आवाज भी फिट नहीं बैठती थी। प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी ने लता मंगेशकर की आवाज को पतली आवाज कहकर अपनी फिल्म शहीद में गाने से मना कर दिया था फिर म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर को फिल्म मजबूर में दिल मेरा तोडा, कहीं का ना छोड़ा गीत गाने को कहा जो काफी सराहा गया । लता मंगेशकर के पिता नहीं चाहते थे कि वो फ़िल्मों के लिये गाने गाये लेकिन लता मंगेशकर बचपन से ही गायक बनना चाहती थीं। लता ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फ़िल्म कीर्ती हसाल के लिये पहली बार गाना गाया था लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फ़िल्मों के लिये गाएं इसलिए इस गाने को फ़िल्म से निकाल दिया गया लेकिन वसंत जोगलेकर लता की प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए । साल 1942 में उनके पिता इस दुनिया को छोड़ गए और लता मंगेशकर के कंधों पर परिवार को संभालने की सारी ज़िम्मेदारी आ गई । पिता की मौत के बाद लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफी संघर्ष करना पड़ा। इसी वजह से लता मंगेशकर ने 1942 से लेकर 1948 तक करीब 8 हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। 40 के दशक में लता मंगेशकर जब फिल्मों में गाना शुरू किया तो वो लोकल पकड़कर अपने घर मलाड जाती थी। वहां से उतरकर पैदल स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज जाती। रास्ते में किशोर दा भी मिलते लेकिन वो एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। किशोर कुमार लता मंगेशकर की ओर देखते रहते। कभी हंसते। कभी अपने हाथ में पकड़ी छड़ी घुमाते रहते। लता मंगेशकर को किशोर कुमार की ये हरकत अजीब लगती थी ।हिंदी सिनेमा में उन्होंने पहला गाना साल 1943 में गाया। ये गाना था फिल्म गजाभाऊ का और इसके बोले थे माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू ।हालांकि इस गाने से लता को कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी। लता मंगेशकर खेमचंद प्रकाश की एक फिल्म में गाना गा रही थी। एक दिन किशोर दा भी उनके पीछे-पीछे स्टूडियो पहुंच गए। लता मंगेशकर ने किशोर कुमार की खेमचंद से शिकायत की। तब खेमचंद ने लता को बताया कि किशोर कुमार अशोक कुमार के छोटे भाई हैं। 1948 में म्यूज़िक कंपोज़र गुलाम हैदर ने लता के बड़ा ब्रेक दिया जिसके बाद उनका संघर्ष का दौर खत्म हुआ और फिल्मी दुनिया में ऐसा सिक्का चला कि लोग उनकी आवाज के दीवाने हो गए। आज भी लता की गायकी सिल्वर स्क्रीन में चार चाँद लगा देती है। फिल्म मजबूर में लता मंगेशकर ने दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा गाना गया। 1949 में उन्होंने फिल्म महल में गाया उनका गाना आएगा आनेवाला बेहद पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने दुलारी, बरसात और अंदाज़ में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। चंद महीनों में ही लता के प्रति लोगों का नजरिया बदला और उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली और फिर इसके बाद उन्हें मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ा। लता मंगेशकर ने फिल्म इंडस्ट्री के सभी दिग्गज म्यूज़िक डायरेक्टर्स और सिंगर्स के साथ काम किया ।1942 से अब तक वो 1000 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों और 36 से भी ज्यादा भाषाओं में गाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। लता मंगेशकर ने 1950 के दौर में कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी रूहानी आवाज़ का जादू बिखेरकर सुनने वालों को सुकून पहुंचाया। लता मंगेशकर ने 1950 के दौर में कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी रूहानी आवाज़ का जादू बिखेरकर सुनने वालों को सुकून पहुंचाया। उस दौरान उन्होंने बैजू बावरा, मदर इंडिया, देवदास और मधुमति जैसी हिट फिल्मों में गाने गाए. फिल्म मधुमति के गाने आजा रे परदेसी के लिए 1958 में लता मंगेशकर को पहला फिल्मफेयर मिला। 60, 70 और 80 के दशक में गाए गए लता मंगेशकर के ज्यादातर गाने ऑल टाइम हिट्स की कैटगरी में आते हैं। कहा जाता है कि बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स और एक्टर्स उनके साथ काम करने के लिए होड़ लगाया करते थे। साल 1977 में आई फिल्म किनारा में लता मंगेशकर नाम गुम जायेगा, चेहरा ये बदल जायेगा, मेरी आवाज़ ही, पहचान है, गर याद रहे गीत गाया। लता मंगेशकर की ये लाइनें उनके हर चाहने वाले को हमेशा याद रहेंगी। लता मंगेशकर ने 1950 के दौर में कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी रूहानी आवाज़ का जादू बिखेरकर सुनने वालों को सुकून पहुंचाया। उस दौरान उन्होंने बैजू बावरा, मदर इंडिया, देवदास और मधुमति जैसी हिट फिल्मों में गाने गाए ।फिल्म मधुमति के गाने आजा रे परदेसी के लिए 1958 में लता मंगेशकर को पहला फिल्मफेयर मिला। 60, 70 और 80 के दशक में गाए गए लता मंगेशकर के ज्यादातर गाने ऑल टाइम हिट्स की कैटगरी में आते हैं। कहा जाता है कि बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स और एक्टर्स उनके साथ काम करने के लिए होड़ लगाया करते थे। साल 1977 में आई फिल्म किनारा में लता मंगेशकर नाम गुम जायेगा, चेहरा ये बदल जायेगा, मेरी आवाज़ ही, पहचान है, गर याद रहे गीत गाया। लता मंगेशकर की ये लाइनें उनके हर चाहने वाले को हमेशा याद रहेंगी। उस दौरान उन्होंने बैजू बावरा, मदर इंडिया, देवदास और मधुमति जैसी हिट फिल्मों में गाने गाए। फिल्म मधुमति के गाने आजा रे परदेसी के लिए 1958 में लता मंगेशकर को पहला फिल्मफेयर मिला।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौताः मोदी नेतृत्व की वैश्विक दृढ़ता

लेखक- ललित गर्ग

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार के परिदृश्य में कोई भी समझौता केवल आंकड़ों या कर-प्रतिशतों तक सीमित नहीं होता, वह राष्ट्र की संप्रभुता, नेतृत्व की दृढ़ता और भविष्य की दिशा का भी संकेतक होता है। भारत और अमेरिका के बीच हालिया व्यापारिक सहमति, जिसके अंतर्गत प्रस्तावित 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है, इसी दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी घटना है। यह निर्णय केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन और भारत की बढ़ती सौदेबाजी क्षमता का प्रमाण है। यहां "देर आए, दुरुस्त आए" की कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है। जब अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर ऊँचे टैरिफ का दबाव बनाया गया था, तब यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को अंततः झुकना पड़ेगा। वैश्विक व्यापार का हालिया इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि बड़ी शक्तियां अक्सर दबाव की राजनीति के माध्यम से अपने हित साधती हैं। किंतु फरवरी 2025 में आरंभ हुई इस व्यापारिक प्रक्रिया का फरवरी 2026 में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना यह दर्शाता है कि भारत ने न तो जल्दबाजी दिखाई और न ही अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किया। भारत ने समय लिया, परिस्थितियों का मूल्यांकन किया और अंततः संतुलित व सम्मानजनक परिणाम प्राप्त किया। 50 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की टैरिफ कटौती का तात्कालिक प्रभाव व्यापारिक जगत और शेयर बाजार में दिखाई दिया। निवेशकों का भरोसा लौटा, निर्यातकों को राहत मिली और बाजार में सकारात्मक संकेत उभरे। किंतु इस निर्णय का वास्तविक महत्व इससे कहीं अधिक व्यापक है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि भारत अब केवल नियमों का पालन करने वाला देश नहीं, बल्कि नियमों के निर्माण और पुनर्परिभाषा में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने वाला राष्ट्र बन चुका है। अमेरिका जैसी महाशक्ति का अपने रुख में नरमी लाना भारत की आर्थिक ताकत, रणनीतिक धैर्य और राजनीतिक आत्मविश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उसमें संवाद है, पर दबाव के आगे समर्पण नहीं। चाहे वह रक्षा सहयोग हो, ऊर्जा सुरक्षा हो या व्यापारिक समझौते-हर क्षेत्र में भारत ने अपने हितों को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस व्यापारिक डील में भी भारत ने बिना झुके, बिना रुके और बिना कमजोर पड़े अपनी शर्तें स्पष्ट रूप से रखीं। यही कारण है कि अंततः अमेरिका को अपने प्रस्तावों में संशोधन करना पड़ा। यह केवल एक व्यापारिक जीत नहीं, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता और नेतृत्व की दृढ़ता का उदाहरण है। इस समझौते से भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक उन्नत स्थिति प्राप्त होगी। कम टैरिफ का अर्थ है कि भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, उनकी पहुंच बढ़ेगी और "मेक इन इंडिया" को नया प्रोत्साहन मिलेगा। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, कृषि-आधारित उत्पाद और उभरते तकनीकी क्षेत्र-सभी को इससे दीर्घकालिक लाभ होने की संभावना है। भारत अब केवल सस्ता श्रम या कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला देश नहीं, बल्कि मूल्यवर्धित उत्पादन और नवाचार की दिशा में अग्रसर अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में जिस संयम और आत्मविश्वास के साथ भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को "निरंतर धैर्य का परिणाम" बताया, वह उनकी कूटनीतिक शैली का सार है। यह समझौता किसी अचानक हुए घटनाक्रम का नतीजा नहीं, बल्कि एक वर्ष तक चली रणनीतिक प्रतीक्षा, विकल्पों के विस्तार और संतुलित संवाद का परिणाम है। मोदी ने स्पष्ट संकेत दिया कि सरकार ने विपक्ष की आलोचनाओं और तात्कालिक दबावों के बावजूद धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति में जल्दबाज़ी अक्सर महंगी पड़ती है। अमेरिका का झुकना किसी भावनात्मक मित्रता का परिणाम नहीं, बल्कि ठोस रणनीतिक विवशता का नतीजा है। बीते एक वर्ष में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके पास विकल्प हैं-रूस के साथ ऊर्जा सहयोग, यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी बढ़ती भूमिका। यदि वाशिंगटन भारत पर एकतरफा दबाव बनाए रखता, तो अमेरिकी कंपनियां दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बड़े बाजार से बाहर हो जातीं। ट्रंप द्वारा 500 अरब डॉलर के आयात, शून्य टैरिफ और रूसी तेल त्यागने जैसे नाटकीय दावे इसी दबाव की राजनीति का हिस्सा थे, जिन्हें भारत ने न तो सार्वजनिक टकराव का मुद्दा बनाया और न ही स्वीकारोक्ति दी। मोदी का इन पर मौन यह दर्शाता है कि भारत इस घटनाक्रम को अंतिम समझौते के रूप में नहीं, बल्कि दिशा-निर्धारण के रूप में देख रहा है। इसके विपरीत, भारतीय विपक्ष इस पूरे प्रकरण में अपनी राजनीतिक अधीरता और रणनीतिक अपरिपक्वता को उजागर करता रहा। उसने टैरिफ को लेकर तात्कालिक लाभ-हानि की भाषा में सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताएं समय, धैर्य और बहुस्तरीय गणनाओं की मांग करती हैं। विपक्ष यह समझने में असफल रहा कि कूटनीति में कभी-कभी पीछे हटना नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करना ही सबसे बड़ा कदम होता है। आज जब अमेरिका को अपना अड़ियल रुख छोड़ना पड़ा है और भारत फिर से वैश्विक प्रतिस्पर्धा की अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिख रहा है, तब यह स्पष्ट है कि मोदी की नीति न केवल दबाव से मुक्त थी, बल्कि दूरदर्शी भी। यही नीति भारत को एक आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और सौदे की शर्तें तय करने वाली शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है।

ईशा ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड जीता

10 मीटर एयर पिस्टल सम्राट को ब्रॉन्ज, पहले दिन भारत ने 9 मेडल जीते

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईशा सिंह ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड जीत लिया है। नई दिल्ली के डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में ईशा ने 239.8 का स्कोर किया। वहीं मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सम्राट राणा को ब्रॉन्ज मेडल मिला।

19वें शॉट में बढ़त बनाई– बुधवार को खेले गए फाइनल में ईशा ने शुरुआती पांच शॉट के बाद सातवें स्थान से वापसी करते हुए 19वें शॉट के बाद निर्णायक बढ़त बनाई। चीनी ताइपे की चेंग येन चिंग को सिल्वर और यू वी एन को ब्रॉन्ज मिला।

सम्राट राणा को ब्रॉन्ज– पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के सम्राट राणा ने 220.3 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस इवेंट में उज्बेकिस्तान के विलामदिर स्वेश्निकोव ने गोल्ड (242.0) और कजाखस्तान के वैलीरी राखीमजान ने सिल्वर जीता।

मनु भाकर को टीम इवेंट में गोल्ड– टीम इवेंट में भी भारत ने शानदार खेल दिखाया। विमेंस एयर पिस्टल टीम में ईशा सिंह, मनु भाकर और सुरुचि सिंह की तिकड़ी ने 1726 अंकों के साथ गोल्ड जीता, जो वियतनाम से 13 अंक अधिक रहा। पुरुष टीम में सम्राट राणा, श्रवण कुमार और वरुण तोमर को सिल्वर मिला।

जोनाथन को गोल्ड– जूनियर वर्ग में जोनाथन गेविन एंटोनी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में 240.9 के स्कोर के साथ व्यक्तिगत स्वर्ण जीता और चिराग शर्मा और प्रियांशु यादव के साथ टीम गोल्ड भी हासिल किया। दिन के आखिरी इवेंट, पुरुष यूथ 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत ने 1–2 फिनिश किया। धैर्य पराशर ने गोल्ड और मंदीप चौहान ने सिल्वर जीता, जबकि दोनों ने गिरीश गुप्ता के साथ मिलकर टीम गोल्ड भी अपने नाम किया।

रणजी ट्रॉफी

क्वार्टर फाइनल मैच से पहले मुंबई को बड़ा झटका, सरफराज खान अस्पताल में भर्ती

मुंबई (एजेंसी)। कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल से पहले मुंबई को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज सरफराज खान बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और वह इस अहम नॉकआउट मुकाबले से बाहर हो गए हैं। सरफराज को बुधवार को तेज बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टीम सूत्रों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे जिससे क्वार्टर फाइनल में उनके खेलने की संभावना बहुत कम है। यह 28 वर्षीय क्रिकेटर इस रणजी सीजन में मुंबई के सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं, उन्होंने मिडिल ऑर्डर में काफी रन बनाए हैं और बल्लेबाजी लाइनअप को स्थिरता दी है। उम्मीद है कि उनकी गैरमौजूदगी से मजबूत कर्नाटक टीम के खिलाफ मुंबई की बल्लेबाजी कमजोर होगी। मुंबई शुक्रवार से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शुरू होने वाले क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक का सामना करेगा। टीम मैनेजमेंट ने अभी तक किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी का नाम नहीं बताया है, हालांकि टीम में लौटने वाले सीनियर खिलाड़ियों से अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाने की उम्मीद है। कई अनुभवी खिलाड़ियों वाली कर्नाटक की टीम मुंबई की इस परेशानी का फायदा उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि दोनों टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने पर नजर गड़ाए हुए हैं।

अंडर 19 वर्ल्ड कप

भारत-इंग्लैंड के बीच फाइनल आज

● भारत का सामना अपराजेय इंग्लैंड से, इस गेंदबाज से बचने की जरूरत

हरारे (एजेंसी)। छठा खिताब जीतने की कोशिश में जुटी भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम जब आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में शुक्रवार को इंग्लैंड से खेलेगी तो उसकी उम्मीदें शानदार फॉर्म में चल रहे अपने बल्लेबाजों पर टिकी होंगी। अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने जीत दर्ज की जिसमें कप्तान आयुष म्हात्रे और सलामी बल्लेबाज आरोन जॉर्ज ने यादगार पारियां खेली। इस जीत से पांच बार की चैम्पियन भारतीय टीम का हौसला बढ़ा है जिसने पिछली बार 2022 में खिताब जीता था।

अपराजेय टीम इंग्लैंड से सामना

भारत ने अमेरिका के खिलाफ पहले ग्रुप मैच से ही बेहतरीन खेल दिखाया है। सेमीफाइनल में 300 से अधिक के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान को हराकर भारतीय टीम ने अपराजेय रिकॉर्ड कायम रखा। अब उसका सामना एक और अपराजेय टीम इंग्लैंड से होना है। भारत को बखूबी पता है कि गत चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंग्लैंड के हौसले बुलंद है और उसे हराना आसान नहीं होगा। भारत को एक ईकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना होगा और नजरें वैभव सूर्यवंशी पर भी लगी होंगी जिनके बल्ले से हो रही आतिशबाजी का जवाब तलाशने के लिए विरोधी गेंदबाज जूझते नजर आए हैं। अगले महीने 15 वर्ष के हो रहे सूर्यवंशी तीन अर्धशतक और एक शतक लगा चुके हैं। इंग्लैंड के सामने उन्हें हालांकि संयम से खेलना होगा क्योंकि मैन्नी लुम्सडेन की अगुवाई में उसके पास मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण है।

भारत को मैन्नी लुम्सडेन से बचना होगा

ऐसे में स्पिनर कनिष्क चौहान और खिलन पटेल की भूमिका अहम हो जाएगा हालांकि टीम संयोजन पिच की स्थिति पर निर्भर करेगा। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले शीर्ष पांच गेंदबाजों में कोई भारतीय नहीं है। इंग्लैंड के मैन्नी लुम्सडेन 15 विकेट लेकर शीर्ष पर है। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने एक ईकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड के लिए बेन मायेस ने एक शतक और दो अर्धशतक समेत 399 रन बनाए हैं। कप्तान थॉमस रियू भी अच्छे फॉर्म में हैं और सेमीफाइनल में आस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक समेत 299 रन बना चुके हैं।

आरोन का शतक, अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया

दुबई (एजेंसी)। भारत ने 10वीं बार अंडर–19 वर्ल्डकप के फाइनल में जगह बना ली है। बुधवार को टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। 6 फरवरी को टीम इंडिया का फाइनल मैच इंग्लैंड के साथ होगा। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 310 रन बनाए हैं। टीम से फैजल शिनोजादा (110 रन) और उजैरुल्लाह नियाजई (नाबाद 101 रन) ने शतकीय पारियां खेलीं। भारत से दीपेश देवेन्द्रन और कनिष्क चौहान ने दो–दो विकेट झटके। 311 रन के जवाब में भारतीय टीम ने ओपनर आरोन जॉर्ज (115 रन) के शतक की बदौलत 41.1 ओवर में 3 विकेट पर जीत हासिल कर ली। टीम से वैभव सूर्यवंशी (68 रन) और कप्तान आयुष म्हात्रे (62 रन) ने फिफ्टी लगाई। भारत ने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज किया है। इतना ही नहीं, भारत ने यूथ वनडे में सबसे बड़ा टारगेट चेज किया है। इस मुकाबले में 620 रन बने। जोकि भारत और अफगानितान की टीमों के बीच यूथ वनडे मैच में सबसे ज्यादा हैं। पिछला रिकॉर्ड 521 रनों का था, जोकि 5 साल पहले 27 दिसंबर 2021 को आईसीसी के दुबई मैदान पर बना था।

टी20 वर्ल्ड कप

भारत के खिलाफ मैच का किया बहिष्कार करने पर पीएम शरीफ की बांग्लादेश ने की सराहना

ढाका (एजेंसी)। आगामी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव बढ़ता दिख रहा है। इसी बीच बांग्लादेश के युवा एवं खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के रुख की खुलकर सराहना की है। नजरुल ने कहा कि भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का पाकिस्तान का फैसला बांग्लादेश के प्रति एकजुटता दर्शाता है, जिसे टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के बाद समर्थन की जरूरत थी। इस बयान ने पूरे मामले को और चर्चा में ला दिया है।

आसिफ नजरुल की प्रतिक्रिया– गुरुवार को आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए पाकिस्तान के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह कदम बांग्लादेश को टी-20 वर्ल्ड कप से हटाए जाने के विरोध में उठाया गया है। नजरुल ने पोस्ट में पाकिस्तान का धन्यवाद करते हुए इसे खेल भावना और आपसी समर्थन का उदाहरण बताया।

शहबाज शरीफ के बयान का हवाला

नज़रुल ने इस्लामाबाद में हुई पाकिस्तान कैबिनेट की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की टिप्पणियों का भी ज़िक्र किया। शरीफ़ ने कहा था कि भारत के खिलाफ़ मैच न खेलने का फैसला राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लिया गया है।

● हरियाणा के खिलाड़ियों का जर्मनी में दबदबा

वेटलिफ्टिंग में भिवानी के संदीप कुमार ने जीता स्वर्ण

● ज्योति प्रकाश ने पाया कांस्य पदक

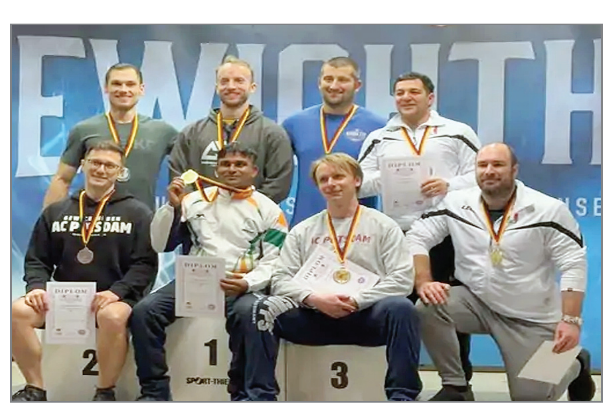

नारनौल (एजेंसी)। जर्मनी के शहर पोट्सडम में आयोजित 5वीं ओपन इंटरनेशनल मास्टर्स वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक अपने नाम किए। इन पदकों में 3 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रतियोगिता में हरियाणा के दो खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया।

हरियाणा मास्टर वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी व नारनौल की कविता ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की ओर से 10 सदस्यों की टीम ने भाग लिया। टीम का नेतृत्व भारतीय मास्टर्स वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी उदय शेट्टी की अगुवाई में किया गया।

हरियाणा के दो खिलाड़ी शामिल

उन्होंने बताया कि हरियाणा के भिवानी जिला के संदीप कुमार ने 65 किलो पुरुष भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की, जबकि हरियाणा के ही ज्योति प्रकाश ने 110 किलो पुरुष भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।

पंजाब के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन

पंजाब के संतोष कुमार ने 110 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा राजविंदर सिंह (79 किलो), चरणजीत सिंह (88 किलो) और पलसाना कुलकर्णी (94 किलो) ने रजत पदक जीते।

बीएसएफ के राजेश बत्रा ने 88 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। आर्मी की 102 इंजीनियर रेजीमेंट के सूबेदार इकबाल सिंह ने प्लस 110 किलो वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि केरल की लेवियस बाबा ने प्लस 86 किलो महिला वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।

पूर्व मंत्री ने दी बधाई

इस प्रतियोगिता में भारतीय मास्टर वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के उपाध्यक्ष संतोष कुमार ने चीफ कोच की भूमिका निभाई। पूर्व मंत्री व नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव सहित कई खेल प्रेमियों और संगठनों ने खिलाड़ियों को बधाई दी।

व्यापार

स्टॉक मार्केट, बैंक या सोना-चांदी कहां पैसा लगाना बेहतर

नई दिल्ली, एजेंसी। बीते कुछ साल से लोगों के निवेश का पैटर्न बदला है। अब लोग बैंकों में बचत करने की बजाए शेयर बाजार में निवेश को तवज्जो दे रहे हैं। अरबपति मुकेश अंबानी ने भी इस पैटर्न को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि यह दौर देश की युवा पीढ़ी के लिए निवेश का एक बहुत बड़ा अवसर होगा। उन्होंने कहा कि भारत पारंपरिक रूप से बचत करने वालों का देश रहा है लेकिन अब समय है कि लोग निवेश करके देश के आगे बढ़ने का फायदा उठाएं। मुकेश अंबानी ने कहा- सोने जैसी फिजिकल एसेट्स के प्रति देश की पुरानी पसंद ने प्रोडक्टिव वेल्थ क्रिएशन को रोक रखा है। पिछले साल भारत ने लगभग 60 बिलियन का सोना और 10-15 बिलियन की चांदी इम्पोर्ट को इंपोर्ट किया था। इसमें से ज्यादातर का इस्तेमाल प्रोडक्टिव तरीके से नहीं किया जाता बल्कि इसे बचत के रूप में रखा जाता है। हालांकि, सोना और चांदी देश की आर्थिक ग्रोथ में सीधे तौर पर हिस्सा लेने में ज्यादा मदद नहीं करते। अंबानी ने कहा कि अगर हम भारतीय बचत करने वालों को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से भारतीय कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मना पाते हैं, तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घरों में पड़े पैसे को ऐसे एसेट्स से हटाकर इक्विटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लगाने का अच्छा मौका है। अंबानी के अनुसार आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए इन्वेस्ट करना अभी भी बहुत मुश्किल है।

चांदी फिर 3 लाख के करीब पहुंची, तगड़ी गिरावट के बाद सोने की भी तेज वापसी

नई दिल्ली, एजेंसी। सोना-चांदी जैसे कीमती धातुओं ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अपनी तेजी को बरकरार रखा। इस दौरान चांदी की कीमतें बढ़कर 2.98 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं और सोना 1.65 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी 14,300 रुपये, या 5.03 प्रतिशत बढ़कर 2,98,300 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। पिछले सत्र में चांदी 2,84,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी तेजी से बढ़ा और 7,400 रुपये या 4.69 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,65,100 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया, जबकि मंगलवार को यह 1,57,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। जानकारों ने कहा, सोने और चांदी ने बुधवार को अपनी तेजी जारी रखी, सोने की कीमतें तीन प्रतिशत से अधिक बढ़ीं और लगभग 1.6 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई।

100 रुपये तक जा सकता है यह शेयर, मजबूत तिमाही नतीजे से एक्सपर्ट बुलिश

नई दिल्ली, एजेंसी। शानदार तिमाही नतीजे के बाद बाजार में लिस्टेड रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के शेयर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश नजर आ रहे हैं। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को शेयर मामूली बढ़त के साथ 63.40 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि, एक्सपर्ट का कहना है कि शेयर में 55 प्रतिशत से ज्यादा उछाल आने वाला है।

एलारा कैपिटल ने रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया शेयर के लिए टारगेट प्राइस 100 रुपये तय किया है। यह वर्तमान कीमत से 55 प्रतिशत से ज्यादा है। ब्रोकरेज एलारा कैपिटल के मुताबिक कंपनी ने दिसंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें ऑपरेटिंग लीवरेज का मजबूत असर दिखा। कंपनी का सेम-स्टोर सेल्स ग्रोथ (स्स्स्ग) 4.5 प्रतिशत रहा। यह पिछले 10 तिमाहियों का उच्च स्तर है। कंपनी ने 31 दिसंबर को खत्म हुए तीन महीनों में 43.54 करोड़ रुपये का नेट लॉस बताया जबकि एक साल पहले यह लॉस 50.4 करोड़ रुपये था।

कंपनी के मुताबिक भारत में कंज्यूमर-फेसिंग बिजनेस में डिमांड धीरे-धीरे बेहतर हो रही है क्योंकि महंगाई कंट्रोल में है और सरकार की कंजम्पशन टैक्स कटौती से खरीदारों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे बच रहे हैं। हालांकि, पश्चिमी फास्ट-फूड ब्रांड्स को लोकल डाइनर्स और क्लाउड किचन से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिससे उन्हें ज्यादा डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं। जैसे-जैसे ग्राहक ज्यादा सेलेक्टिव हो रहे हैं, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया का मकसद कीमतों को सही रखकर उन्हें वापस लाना है इन कोशिशों से बर्गर किंग को सेम-स्टोर सेल्स में 4.5 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल करने में मदद मिली, जो कम से कम 12 महीनों से खुले स्टोर्स की सेल्स को दिखाता है, जो पिछले क्वार्टर की 2.8 प्रतिशत ग्रोथ से ज्यादा तेज है। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया का ऑपरेशन से कुल रेवेन्यू, जो इंडोनेशिया में भी रेस्टोरेंट चलाता है, लगभग 12 प्रतिशत बढ़कर 715 करोड़ रुपये हो गया। पिछले महीने, कंपनी ने कहा कि रियल एस्टेट से लेकर रेस्टोरेंट ग्रुप इंस्पिरा ग्लोबल फर्म में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी के लिए 3416 करोड़ रुपये तक का निवेश करेगा, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी फर्म एवरस्टोन अपनी हिस्सेदारी बेच रही है।

1 पर 3 शेयर बोनस देगी मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर

नई दिल्ली, एजेंसी। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड के शेयर फोकस में हैं। कंपनी के शेयर शुरुआती कारोबार में ही 2 पर्सेंट तक चढ़कर 1,928.50 रुपये पर आ गए थे। दरअसल, कंपनी के बोर्ड ने पहली बार बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दी है। कंपनी 3:1 के रेशियो में बोनस इश्यू लाएगी। यानी जिन निवेशकों के पास 1 शेयर है, उन्हें 3 अतिरिक्त शेयर मुफ्त मिलेंगे। सभी शेयर 2 के फेस वैल्यू के होंगे। हालांकि, इसके लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान अभी नहीं हुआ है। बोनस शेयर का यह प्रस्ताव कंपनी की आम बैठक और जरूरी वैधानिक व नियामकीय मंजूरियों के बाद लागू होगा। निवेशकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कंपनी अब तक अपने शेयरधारकों को 40 प्रति शेयर का डिविडेंड दे चुकी है, जिसकी शुरुआत साल 2020 से हुई थी। बोनस इश्यू का फैसला यह दिखाता है कि कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है और मैनेजमेंट भविष्य को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। दिसंबर तिमाही के नतीजों की बात करें तो मेट्रोपोलिस ने मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर 429.19 करोड़ पहुंच गया। वहीं, मुनाफा भी 32 प्रतिशत की बढ़त के साथ 52.67 करोड़ रहा। कंपनी के मुताबिक, मरीजों की संख्या में 14 प्रतिशत और टेस्ट वॉल्यूम में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)